एक्ज़िम बैंक EXIM BANK
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

एक्ज़िमिअस
निर्यात लाभ

सितंबर 2018
खंड XXXIV अंक III

इस अंक में

1-3 ब्रिक्स और अफ्रीका: सतत विकास को बढ़ावा देने में सामूहिकता की भूमिका
4 वृहत्तर आर्थिक सहयोग की ओर भारत-रूस: ऐतिहासिक मैत्री के 70 साल
5 भारत-लैक व्यापार: रुझान और संभावनाएं
6 क्षेत्रीय फोकस: मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका
7 भारतीय हथकरघा उद्योग
8 पर्यटन क्षेत्र: रुझान और संभावनाएं
9 एक्ज़िम बैंक की ऋण-व्यवस्थाएं
10 तिमाही गतिविधियां
11 अफ्रीका में चीनी वित्तपोषण का बदलता स्वरूप: क्या सावधान हो रहा है चीन?
12 एक्ज़िम बैंक गतिविधियां
13 देशों का सूक्ष्मावलोकन
14 मुद्रा की प्रवृत्तियां
15 भारतीय अर्थव्यवस्था का परिदृश्य
16 व्यापार और भागीदारी अवसर

भारतीय निर्यात-आयात बैंक
का तिमाही प्रकाशन
www.eximbankindia.in

प्रधान कार्यालय :
केंद्र एक भवन, 21 वीं मंज़िल,
विश्व व्यापार केन्द्र संकुल,
कफ़ परेड, मुंबई 400 005
Tel.: 022 2217 2600
Email : ccg@eximbankindia.in

ब्रिक्स और अफ्रीका: सतत विकास को बढ़ावा देने में सामूहिकता की भूमिका

अफ्रीका तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं वाला महाद्वीप है। आज अफ्रीकी देश अंतरराष्ट्रीय पटल पर नई और उभरती वैश्विक ताकतों के साथ संपर्क बढ़ा रहे हैं और यह महाद्वीप विकास के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। उभरती वैश्विक ताकतों के साथ संपर्कों में ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) देशों और एक समूह के रूप में उनकी क्षमता की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

वर्ष 2001 में जिम ओ'नील (गोल्डमैन सैक्स) ने जब ब्रिक्स का संक्षिप्त नाम दुनिया के सामने रखा था, तब से आज तक इस समूह ने एक लंबी यात्रा तय की है। यही वह संक्षिप्त नाम था जिसने ब्रिक्स देशों के बीच वृहद सहयोग की बुनियाद रखी और इन देशों के आर्थिक-राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए यह एक ऐसे सहयोग तंत्र के रूप में विकसित हुआ, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव लाने की संभावनाएं हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वैश्विक आबादी का 41.1% हिस्सा इन ब्रिक्स देशों में ही रहता है, दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 29.6% ब्रिक्स देश ही हैं, वैश्विक जीडीपी में 22.2% और वैश्विक व्यापार में 16.4% योगदान इन्हीं देशों का है।

अफ्रीका में ब्रिक्स: वाणिज्यिक संबंधों पर एक नजर

2009 के पहले ब्रिक सम्मेलन (2011 में ब्रिक्स सम्मेलन) की शुरुआत से अब तक ब्रिक्स के विकास के साथ-साथ अफ्रीका और ब्रिक्स देशों के बीच संपर्क बढ़ा है। ब्रिक्स-अफ्रीका व्यापार 2009 के 157.3 अरब यूएस डॉलर से बढ़कर 2017 में 289 अरब यूएस डॉलर हो गया। इसमें 7.9% की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई। इस अवधि के दौरान, अफ्रीका के वैश्विक व्यापार में ब्रिक्स का योगदान 20.4% से बढ़कर 33% हो गया। जनवरी 2003 से जुलाई 2018 के दौरान अफ्रीका में 228 बिलियन यूएस डॉलर निवेश के साथ कुल पूंजीगत व्यय का 20.3% हिस्सा ब्रिक्स का ही रहा।

ब्रिक्स-भारत व्यापार के आंकड़े अफ्रीका में चीन की जबर्दस्त उपस्थिति की ओर संकेत करते हैं। चीन के बाद भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और रूस का स्थान है। इस महाद्वीप में चीन का व्यापार ब्रिक्स के सामूहिक व्यापार से भी अधिक है। सामूहिक रूप से ब्रिक्स का व्यापार संतुलन बेहतर रहा। हालांकि 2010 से 2014 के दौरान व्यापार संतुलन अफ्रीका के पक्ष में रहा था। इस रुझान को 2010 से 2014 के दौरान तेल और संबंधित वस्तुओं की कीमतों में आए उछाल और तेल, गैस तथा संबंधित वस्तुओं के निवल आयातकों पर इस उछाल के प्रभाव के जरिए बेहतर समझा जा सकता है। ब्रिक्स द्वारा सामूहिक रूप से अफ्रीका से मुख्यतः प्राथमिक वस्तुओं का आयात किया जाता है और पूंजीगत वस्तुओं तथा वैल्यू एडेड वस्तुओं का निर्यात किया जाता है।

अफ्रीका महाद्वीप में विदेशी पूंजीगत व्यय में भी चीन का बोलबाला है। एफडीआई मार्केट्स डाटाबेस[1] के अनुसार, जनवरी 2003 से जुलाई 2018 के दौरान अफ्रीका में 409 परियोजनाओं में चीन का विदेशी पूंजीगत व्यय 94 अरब यूएस डॉलर रहा। इसके बाद भारत, रूस और दक्षिण अफ्रीका का स्थान रहा, जिनका अफ्रीका में विदेशी पूंजीगत व्यय क्रमशः 542 परियोजनाओं में 46.3 अरब यूएस डॉलर, 88 परियोजनाओं में 40.1 अरब यूएस डॉलर और 475 परियोजनाओं में 38.2 अरब यूएस डॉलर रहा। इस अवधि के दौरान 9.6 अरब यूएस डॉलर के पूंजीगत व्यय के साथ ब्राजील का पूंजीगत व्यय तुलनात्मक रूप से काफी कम रहा।

हालांकि ब्रिक्स ने पूरे महाद्वीप में विभिन्न परियोजनाओं में निवेश किया, लेकिन पूंजीगत व्यय कुछ एक अर्थव्यवस्थाओं में ही केंद्रित रहा। ब्रिक्स विदेशी पूंजीगत व्यय का 77.3% हिस्सा महाद्वीप के शीर्ष 10 देशों में ही रहा। अफ्रीकी महाद्वीप में ब्रिक्स तथा वैश्विक एफडीआई के प्रमुख प्राप्तकर्ता देशों में मिस्र, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, अंगोला, मोजाम्बिक, घाना और मोरक्को शामिल रहे।

ब्रिक्स विकास सहयोग रणनीतियां

द्विपक्षीय स्तर पर देखा जाए तो अफ्रीकी महाद्वीप में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास क्षेत्र में चीन की बड़ी मौजूदगी है। बड़े पैमाने की जलविद्युत ऊर्जा और अन्य अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं सहित

[1] *एफडीआई मार्केट्स किसी ऐसे नई भौतिक परियोजना में निवेश अथवा मौजूदा निवेश में विस्तार का लेखा-जोखा रखता है, जिनसे नए रोजगारों और पूंजीगत निवेश का सृजन होता है। संयुक्त उद्यमों को तभी शामिल किया जाता है, जब उनसे भौतिक परिचालन हो रहा हो।*

बिजली और सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे जैसी परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की परियोजनाओं में चीनी धन लगा है और चीनी कंपनियां इन परियोजनाओं का निष्पादन कर रही हैं। भारतीय कंपनियों की मौजूदगी बिजली, अक्षय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल और औद्योगिक मशीनरी, पुर्जे और टूल्स जैसे क्षेत्रों में है।

ब्राजील कृषि और ऊर्जा क्षेत्र में हासिल की गई अपनी विशेषज्ञता को देखते हुए इस महाद्वीप में कृषि, कृषि-प्रसंस्करण, जैव-ईंधन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे क्षेत्रों में क्षमता निर्माण पर सबसे अधिक काम कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने समूचे दक्षिणी अफ्रीका में बिजली उत्पादन और वितरण के लिए एक परिचालनरत क्षेत्रीय विद्युत इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्रिक्स देशों के इन प्रयासों का पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इससे उन्हें आधुनिक परिवहन नेटवर्क और बेहतर बिजली मिलने लगी है। इसके साथ ही महाद्वीप में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण भी हो सका है।

ब्रिक्स देशों के मध्य विकास सहयोग में तकनीकी सहयोग भी एक अहम पहलू बनकर उभरा है। अफ्रीकी छात्रों द्वारा उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और प्रोफेशनल प्रशिक्षण के लिए ब्रिक्स देशों को चुनना ब्रिक्स देशों के महत्त्व को उजागर करता है। उच्च शिक्षा के लिए एक चौथाई से अधिक अफ्रीकी छात्र ब्रिक्स देशों में ही जाते हैं। इनमें भी सबसे अधिक चीन और दक्षिण अफ्रीका जाने वाले छात्र हैं।

विकास सहयोग के लिए ब्राजील की रणनीति, मानवीय क्षमताओं और सरकारी संस्थाओं को सुदृढ़ बनाते हुए आर्थिक विकास, ढांचागत बदलाव और सामाजिक समावेशन के उद्देश्य से काम करने की है। ब्राजील में नवोन्मेषी सार्वजनिक नीतियों पर आधारित पहलें विशेष रूप से लुसोफोन अफ्रीका सहित इस महाद्वीप के कुछ ऐसे विकासशील देशों के लिए काफी कारगर साबित हो सकती हैं, जो ब्राजील से किसी भी बिंदु पर ऐतिहासिक, जनसांख्यिक, भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक रूप से जुड़े हैं। तकनीकी सहयोग में कृषि, जैव ईंधन और कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र का ब्राजील के विकास सहयोग में प्रमुख स्थान है।

अफ्रीका में विकास वित्त के प्रत्यक्ष संवितरण से रूस ज्यादातर बचता रहा है। इस संवितरण के प्रबंधन के लिए रूस की कोई केंद्रीय एजेंसी नहीं है। अभी तक विकास सहयोग का प्रबंधन विकास सहयोग के मौजूदा बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से ही होता आया है। इनमें ओईसीडी, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी बहुपक्षीय एजेंसियां शामिल हैं। अफ्रीका में रूस का विकास सहयोग मुख्यतः खाद्य सहायता, मानवीय सहयोग और क्षमता निर्माण के रूप में ही रहा है।

भारत और चीन ने विकास सहयोग की एक नई बानगी पेश की है। दोनों ही देशों ने विकास सहयोग को एक वृहद वाणिज्यिक संबंधों से जोड़ने का काम किया है। ताकि व्यापार और निवेश में परस्पर दोनों पक्षों को लाभ मिले। अफ्रीका में भारत का विकास सहयोग मुख्यतः ऋण-व्यवस्थाओं तथा भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईटीईसी) के माध्यम से परिचालित है। अफ्रीका में क्षमता निर्माण के लिए आईटीईसी के जरिए एक संस्थागत व्यवस्था विकसित हुई है और विदेशी प्रोफेशनलों व छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम सुलभ हुए हैं। ऋण-व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) द्वारा प्रदान की जाने वाली एक वित्तीय व्यवस्था है, जो विदेशी वित्तीय संस्थाओं, संप्रभु सरकारों और अन्य विदेशी संस्थाओं को रियायती ऋण प्रदान करता है। यह ऋण विकास और इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं, उपकरणों, वस्तुओं और सेवाओं के भारत से आयात के लिए दिया जाता है। भारत ने निर्यात संवर्धन और नए बाजारों में निवेश के साथ संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण के जरिए अफ्रीकी महाद्वीप में अपना महत्त्वपूर्ण विस्तार किया है।

अफ्रीका में चीन का विकास सहयोग सबसे अधिक विस्तृत है। इस महाद्वीप में चीन के अनुदान हैं, रियाती ऋण हैं, कर्ज माफी है और रणनीतिक ऋण-व्यवस्थाएं हैं। इन सबके जरिए चीनी कंपनियों को अफ्रीकी सरकारों द्वारा मंजूर की गई परियोजनाओं के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में मदद मिलती है। चीनी कंपनियां अफ्रीकी महाद्वीप में कई बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं और महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं सहित विभिन्न परियोजनाओं का निष्पादन कर रही हैं।

दक्षिण अफ्रीका को उसकी राजनीतिक-आर्थिक नेतृत्व क्षमता और अफ्रीकी महाद्वीप में बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विकास सहयोग में अपने सक्रिय योगदान के चलते दक्षिणी अफ्रीका में प्रायः एक महत्त्वपूर्ण देश के रूप में देखा जाता है। दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा योगदान अफ्रीकी संघ, अफ्रीका के विकास के लिए नई भागीदारी एजेंसी अफ्रीकी संघ, दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय और दक्षिणी अफ्रीकी कस्टम्स संघ में है। इसके अलावा, दक्षिण अफ्रीका अपने विकास कार्यक्रमों को अफ्रीकी पुनर्जागरण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग कोष (एआरएफ) के माध्यम से चलाता है। सहयोग, लोकतंत्र, सुशासन, प्रतिकूल समस्याओं के निदान, सामाजिक-आर्थिक विकास, मानवीय और आपदा राहत, तकनीकी सहयोग और क्षमता विकास जैसी फंडिंग गतिविधियों के लिए एआरएफ का एक बड़ा मैंडेट है।

ब्रिक्स वाणिज्यिक संबंधों का समन्वयक - ब्रिक्स विकास बैंक

ब्रिक्स ने अफ्रीकी बाजारों में अपने विस्तार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संसाधनों का इस्तेमाल किया है। विभिन्न वाणिज्यिक गतिविधियों, विशेष रूप से इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए ऋण-व्यवस्थाओं की इस विस्तार में बड़ी भूमिका है। महत्त्वपूर्ण रणनीतिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने तथा तकनीकी हस्तांतरण के लिए वित्त और सहयोग प्रदान करने में ब्रिक्स विकास वित्त संस्थाओं और निर्यात ऋण एजेंसियों की भी अहम भूमिका रही है।

ब्राजील के बीएनडीईएस और ब्राजीलियाई कोष तथा गारंटी प्रबंधन एजेंसी; रूस के वेनेश्कोनॉम बैंक और रूसी निर्यात बीमा एजेंसी; भारत के एक्ज़िम बैंक और ईसीजीसी (पूर्व में निर्यात ऋण बीमा निगम); चीन के चीनी औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक, चीनी विकास बैंक, चीनी निर्यात-आयात बैंक और चीनी निर्यात एवं ऋण बीमा निगम; तथा दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी अफ्रीकी विकास बैंक, औद्योगिक विकास निगम और दक्षिण अफ्रीकी निर्यात ऋण बीमा निगम इसके उदाहरण हैं।

अफ्रीका में ब्राजील के वाणिज्यिक विस्तार में बीएनडीईएस की अहम भूमिका है। घरेलू निर्यात

उन्मुख कंपनियों, ब्राजीलियाई संस्थाओं और अफ्रीकी बाजार के बीच पारस्परिक संपर्क के लिए बीएनडीईएस बैंक एक प्रमुख संस्था है। बीएनडीईएस के कार्यक्रमों ने ब्राजीलियाई कृषि अनुसंधान निगम और नेशनल सर्विस फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को उनके अफ्रीका उन्मुख कार्यक्रमों के लिए सशक्त बनाया है। इसके साथ ही बीएनडीईएस ने पेट्रोलैब्स, फायोक्रूज, ओडेब्रेश्ट, वेल जैसी संस्थाओं के लिए अफ्रीकी ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवा बाजार में निवेश को सुगम बनाया है।

अफ्रीका में रूस अपना निवेश अन्य बैंकों के साथ मिलकर सरकारी स्वामित्व वाले वेनेश्कोनॉम बैंक के जरिए बढ़ा रहा है। रूसी कंपनियों को अफ्रीकी देशों में निवेश के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। साथ ही रूसी निर्यातों, विशेष रूप से हथियार उद्योग से निर्यातों को बढ़ाने में भी सहयोग प्रदान किया जाता है।

अफ्रीकी देशों में भारतीय व्यापार और निवेश को सुगम बनाने में एक्ज़िम बैंक की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत सरकार की ओर से एक्ज़िम बैंक द्वारा दी जाने वाली ऋण-व्यवस्थाओं के प्राप्तकर्ताओं में अफ्रीकी महाद्वीप प्रमुख रहा है। जून 2018 तक कुल 22.56 अरब यूएस डॉलर की ऋण प्रतिबद्धताओं में से 9.3 अरब यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्थाएं अफ्रीका को रही हैं। ये रियायती ऋण-व्यवस्थाएं भारत और अफ्रीका के बीच आधिकारिक और वाणिज्यिक दोनों संबंधों को बढ़ाने में बेहद महत्त्वपूर्ण रही हैं।

अफ्रीका में परियोजनाओं का निष्पादन करने वाली भारतीय कंपनियों के संवर्धन और वित्तपोषण में एक्ज़िम बैंक की अहम भूमिका रही है। राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत क्रेता ऋण कार्यक्रम के जरिए बैंक ने भारत से परियोजना निर्यातों को बढ़ाने पर जोर दिया है। यह कार्यक्रम भारतीय निर्यातकों को दायित्व रहित आधार पर वित्तपोषण का विकल्प प्रदान करता है। एक्ज़िम बैंक ने दक्षिण अफ्रीका, केन्या, मॉरीशस, नाइजीरिया, सूडान, मिस्र, जांबिया, मोरक्को, यूगांडा और तंजानिया जैसे देशों में कई संयुक्त उद्यमों और पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों को भी सहयोग प्रदान किया है। इन देशों को यह सहयोग फार्मास्युटिकल्स, रसायन, उर्वरक, टेक्सटाइल्स, कृषि आधारित उत्पाद, प्लास्टिक और रबर उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग सामान, साइकिल और टेलीकॉम सिस्टम जैसे विभिन्न क्षेत्रों में दिया गया है। बैंक ने अफ्रेक्ज़िम बैंक और जांबिया विकास में इक्विटी भी ली है और इस तरह इस क्षेत्र में आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए संस्थागत संबंधों का नेटवर्क भी विकसित किया है।

चीन ने अफ्रीका को जनवरी 2000 से दिसंबर 2015 के बीच सीडीबी, चीनी एक्ज़िम बैंक, आईसीबीसी और अन्य वाणिज्यिक बैंकों जैसी अपनी वित्तीय संस्थाओं के नेटवर्क के जरिए लगभग 94.4 अरब यूएस डॉलर के रियायती और वाणिज्यिक ऋण प्रदान किए हैं। चीन की 'विदेश चलो' और 'बेल्ट एवं रोड पहल' जैसी सरकारी नीतियों में विहित अनुसार चीनी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की दूसरे देशों में उपस्थिति बढ़ाने के लिए वित्तीय संस्थाओं के इस नेटवर्क को सरकारी सहयोग प्राप्त है।

अफ्रीका के साथ व्यापार और निवेश बढ़ाने में दक्षिण अफ्रीका के डीबीएसए और आईडीसी की अहम भूमिका रही है। इन संस्थाओं में अफ्रीकी महाद्वीप में औद्योगिक विस्तार में संलग्न दक्षिण अफ्रीकी देशों को ऋण और निजी क्षेत्र की कंपनियों को वित्तीय सहयोग प्रदान करने का प्रावधान है। डीबीएसए ने इस क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को ऋण प्रदान करते हुए 1997 में अपना मैंडेट और अधिक विस्तृत दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्र तक बढ़ा लिया था। इसके अतिरिक्त दक्षिण अफ्रीका, विकास सहयोग में समन्वय के लिए दक्षिण अफ्रीकी विकास भागीदारी एजेंसी नाम से एक अंब्रेला एजेंसी स्थापित करने के लिए भी प्रयासरत है।

अफ्रीकी विकास के नए मॉडल की दिशा में ब्रिक्स और अफ्रीका

ब्रिक्स विकास को-ऑपरेशन का विश्लेषण बताता है कि ब्रिक्स के हर देश ने अफ्रीकी महाद्वीप के साथ संबंधों में विस्तार के लिए अपना अलग तरीका अपनाया है। ब्रिक्स सदस्य देशों और सामूहिक रूप से उनके मैंडेट में कुछ समानताएं उभरी हैं। जैसे- बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए वित्त, कृषि क्षेत्र में तकनीकी सहयोग और मानव संसाधन विकास क्षेत्र में क्षमता निर्माण। इन समानताओं का विभिन्न सहयोग तंत्रों के अंतर्गत लाभ उठाया जा रहा है। ब्रिक्स फ्रेमवर्क के अंतर्गत ही विकसित हुआ न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) सभी विकासशील देशों के लिए महत्त्वपूर्ण है। दक्षिण अफ्रीका में एनडीबी का एक क्षेत्रीय कार्यालय है, जो बैंक को अफ्रीकी महाद्वीप में उपस्थिति बढ़ाने में मददगार होगा।

आने वाले समय में, औद्योगिक गतिविधियों, प्रक्रियाओं, तकनीकों और प्रौद्योगिकी के विकास तथा क्रियान्वयन को प्रोत्साहित करने वाली गतिविधियों में एकरूपता और समन्वय बनाए रखना ब्रिक्स के लिए एक प्रमुख चुनौती हो सकती है। ब्रिक्स द्वारा अपने-अपने स्तर पर दिया जाने वाला विकास सहयोग कभी-कभी मिश्रित ऋणों के रूप में होता है। चूंकि यह सहयोग सभी ब्रिक्स देश अपने-अपने स्तर पर करते हैं, इसलिए ये सहयोग उनकी अपनी विदेश नीति के अनुसार होते हैं। लेकिन ब्रिक्स विकास सहयोग तंत्र के अंतर्गत विकास सहयोग प्रदान करने पर विदेश नीति संबंधी इन पहलुओं पर असर पड़ सकता है।

इस सबके बावजूद, ब्रिक्स देशों के पास समय है कि वे अपनी-अपनी भू-राजनीतिक होड़, आर्थिक-राजनीतिक असमानताओं को किनारे कर आगे बढ़ें और अपने दायरे को अधिक विस्तृत बनाएं। हाल ही में हुआ ब्रिक्स सम्मेलन इस बात की ओर संकेत करता है कि अफ्रीकी महाद्वीप के सतत विकास के लिए ब्रिक्स देश सामूहिक रूप से प्रतिबद्ध हैं।

जुलाई 2017 में दक्षिण अफ्रीका में इस ब्रिक्स समूह का 10वां सम्मेलन हुआ था। इसकी थीम ही थी- अफ्रीका में ब्रिक्सः समावेशी विकास में सबका साथ और चौथी औद्योगिक क्रांति में सबका विकास। यह थीम संकेत है कि अफ्रीकी महाद्वीप के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए उभरती वैश्विक शक्तियां पारस्परिक हित के साथ किस तरह आगे आ रही हैं। चौथी औद्योगिक क्रांति के फ्रेमवर्क के अंतर्गत ब्रिक्स-अफ्रीका भागीदारी की अवधारणा अपने आप में बेहद महत्त्वपूर्ण है। यह भागीदारी विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष जैसे समसामयिक महत्त्व के क्षेत्रों में सहयोग पर केंद्रित है। इससे इस महाद्वीप में सामाजिक-आर्थिक बदलाव की भरपूर संभावनाएं जन्म ले रही हैं।

4 वृहत्तर आर्थिक सहयोग की ओर भारत–रूस: ऐतिहासिक मैत्री के 70 साल

भारत–रूस की ऐतिहासिक मैत्री के 70 साल पूरे हो चुके हैं। दोनों देशों ने 2017 में अपने ऐतिहासिक राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मनाई। रूस लंबे समय से भारत का मित्र और एक अहम साझीदार रहा है। यह भागीदारी व्यापार और अर्थव्यवस्था से लेकर तकनीकी सहयोग, ऊर्जा, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और मानव संसाधनों के आदान–प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में रही है। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के इन अनथक प्रयासों के बावजूद आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए अब भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, जिनकी ओर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया है और उन क्षेत्रों में काफी संभावनाएं हैं। हालांकि बीते एक दशक के दौरान भारत–रूस का द्विपक्षीय व्यापार लगभग दोगुना हो गया है। यह 2008 में 5.5 अरब यूएस डॉलर था, जो 2017 में बढ़कर 10.1 अरब यूएस डॉलर हो गया। लेकिन रूस के वैश्विक निर्यातों और आयातों में रूस के अन्य भागीदार देशों के हिस्से को देखते हुए भारत का हिस्सा तुलनात्मक रूप से काफी कम है। इसके अतिरिक्त, रूस के साथ भारत के द्विपक्षीय निवेश संबंधों में एक धीमापन है। इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि अप्रैल 2000 से मार्च 2018 के दौरान भारत के एफडीआई वैश्विक आवक में रूस का हिस्सा मात्र 0.33 प्रतिशत ही रहा। वहीं, अप्रैल 1996 से मार्च 2018 के दौरान रूस में संयुक्त उद्यमों और पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों में भारत का संचयी मंजूर निवेश इसके कुल वैश्विक निवेश का केवल 1.6 प्रतिशत रहा। यह निवेश भी मुख्यतः तेल और गैस तथा फार्मस्युटिकल क्षेत्रों में केंद्रित रहा।

द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना

भारत, रूस का 20वां सबसे बड़ा निर्यातक है। 2017 में रूस द्वारा कुल आयात का 1.3 प्रतिशत भारत से ही आयात किया गया। इसी तरह रूस, भारत का 16वां सबसे बड़ा निर्यातक है। 2017 में रूस के कुल निर्यातों का 1.8 प्रतिशत भारत को निर्यात किया गया। हालांकि, रूस को भारत के शीर्ष निर्यातों में फार्मास्युटिकल्स, मशीनरी और यांत्रिक उपकरण, एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरण जैसे सामान शामिल हैं, लेकिन रूस में इन उत्पादों की मांग को देखते हुए इनके निर्यातों की पूर्ण संभावनाओं को अभी तक नहीं भुनाया नहीं गया है। इसके अतिरिक्त, रूस के साथ भारत के बढ़ते व्यापार घाटे की समस्या से निपटना भी अत्यावश्यक है, जो पिछले एक दशक के दौरान दोगुना हो गया है। 2008 में यह 3.4 अरब यूएस डॉलर था, जो 2017 में बढ़कर 5.8 अरब यूएस डॉलर हो गया है। विशेष रूप से भारत द्वारा रूस को निर्यातों को बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ाना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले ऐसी वस्तुओं को चिह्नित करना होगा, जिनकी रूस में अच्छी मांग हो और भारत उन वस्तुओं का वैश्विक निर्यात कर सके। रूस को निर्यात की जाने वाली ऐसी संभावित वस्तुओं को एक्ज़िम बैंक के भारत–रूस व्यापार संबंधः हालिया रुझान और संभावनाएं शीर्षक वाले शोध अध्ययन में चिह्नित किया गया है। इसमें प्रत्येक श्रेणी में 6 डिजिट तक के एचएस कमोडिटी कोड वाले निर्यात की संभावनाओं वाले उत्पादों को चिह्नित किया गया है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- मशीनरी और यांत्रिक उपकरण (एचएस–84)
- इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरण (एचएस–85)
- रेलवे और ट्रामवे को छोड़कर अन्य वाहन (एचएस–87)
- प्लास्टिक और प्लास्टिक की वस्तुएं (एचएस–39)
- ऑप्टिकल, फोटोग्राफिक, सिनेमैटोग्राफिक उपकरण (एचएस–90)
- लोहा और स्टील और इनके सामान (एचएस–72 और एचएस–73)
- फल और मेवा (एचएस–8)
- रबर और रबर की वस्तुएं (एचएस–40)
- जहाज, नाव और अन्य फ्लोटिंग स्ट्रक्चर (एचएस–89)
- जूते–चप्पल, घुटने पर बांधने वाली पट्टियां और अन्य सामान (एचएस–64)

व्यापार लोजिस्टिक्स में सुधार करना

भारत और रूस के बीच व्यापार को लेकर कुछ चुनौतियां व्यापार लोजिस्टिक्स में हो सकती हैं। पानी या भूमार्ग से रूस को भारत द्वारा माल की आपूर्ति कराने में 40 से 55 दिन लग सकते हैं। इतना समय लगने से निश्चित रूप से लागत भी बढ़ जाती है। इसलिए रूसी व्यापारियों के लिए भारत पहली पसंद नहीं बन पाता है और वे यूरोप या चीन से कम समय में वही माल आयात करने को प्रवृत्त होते हैं। अंतरराष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण परिवहन गलियारे का समय पर शुरू होना इस संबंध में एक जरूरी पहलू है, जिससे माल तेजी से पहुंच सकेगा और व्यापार सुगम हो सकेगा। इसके साथ ही, व्यापार को सुगम बनाने के लिए ग्रीन कॉरीडोर परियोजना को परिचालित करना भी व्यापार लोजिस्टिक में सुधार का अहम कारक होगा।

निवेश में निजी क्षेत्र की सहभागिता बढ़ाना

भारत के निवेश भागीदार के रूप में रूस की सहभागिता सीमित रही है और कुछ एक क्षेत्रों में ही केंद्रित रही है। सॉफ्टवेयर और आईसीटी, ऑटोमोटिव और एयरोस्पेस आदि जैसे क्षेत्रों में भी पर्याप्त संभावनाएं हैं। लेकिन इन क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया गया है। इस संबंध में, भारत और रूस को चाहिए कि वे इन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र निवेश को बढ़ाएं और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा संयुक्त उद्यमों के लिए भागीदारी करें। वर्तमान में, द्विपक्षीय आर्थिक संबंध मोटे तौर पर सरकारी नियंत्रण वाली कंपनियों के सहयोग पर ही आधारित हैं, जो दोनों देशों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच आपसी संपर्कों में रुकावट पैदा सर सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि दोनों देश अपने यहां व्यवसाय स्थापित करने की शर्तों को सुगम बनाने के लिए व्यवसाय वार्ताओं में नवोद्यमों सहित निजी क्षेत्र की कंपनियों को आकर्षित करें।

बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ाना

बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में सामने आने वाली चुनौतियों से दोनों देशों को मिलकर निपटना जरूरी है। इसके लिए दोनों को मिलकर नए उपाय तलाशने की जरूरत है। इसका एक उपाय दिल्ली–मुंबई औद्योगिक गलियारा, स्मार्ट सिटी योजना और माल ढुलाई गलियारा (फ्रेट कॉरिडोर), टेलीकॉम, बिजली और सड़क जैसे विस्तृत क्षेत्रों वाली भारत की प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में रूसी निवेश को बढ़ाना हो सकता है। इन क्षेत्रों और उच्च प्रौद्योगिकी वाले उत्पादों के संयुक्त विनिर्माण में निवेश के लिए विशेषीकृत निवेश निधियों को प्रोत्साहित करना एक अन्य उपाय हो सकता है। वहीं दूसरी ओर, रूस में फार्मास्युटिकल्स, उर्वरक, कोयला और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों तथा औद्योगिक पार्कों में भारतीय भागीदारी को भी ऐसे ही उपायों से बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, जहाजनिर्माण, बंदरगाह विकास, इनलैंड जलमार्ग, उच्च गति वाले रेलवे आदि जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और अनुभव हस्तांतरण के जरिए परियोजनाओं के संयुक्त विकास की भी अनेक संभावनाएं हैं।

लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र (लैक) का संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वर्ष 2000 के 2.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2017 में 5.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो गया। वैश्विक वस्तु कीमतों में बढ़ोत्तरी और अच्छी घरेलू खपत के चलते लैक क्षेत्र में यह तेजी बने रहने की उम्मीद है। इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में 2017 में उछाल आया और इसमें 1.3% की विकास दर दर्ज की गई। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने वैश्विक वस्तु कीमतों और वैश्विक मांग में तेजी को देखते हुए 2018 में 2% और 2019 में 2.8% की अच्छी वृद्धि का अनुमान जताया है।

वैश्विक वृद्धि और वस्तुओं की कीमतों में रिकवरी की संभावनाओं के मद्देनजर लैक क्षेत्र अपने व्यापार में फिर से तेजी की उम्मीद कर रहा है। इस क्षेत्र के व्यापार में 2016 की तुलना में 2017 में 11.5% की वृद्धि हुई। इसका निर्यात 10.8% बढ़ा और आयात में 12.3% की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई।

लैक क्षेत्र में मेक्सिको सबसे बड़ा निर्यातक है। इस क्षेत्र के कुल निर्यात का 41.6% मेक्सिको से ही निर्यात होता है। इसके बाद ब्राजील का स्थान है, जो कुल निर्यात का 22.1% निर्यात करता है। इसके बाद चिली (7%), अर्जेंटीना (5.9%), पेरू (4.5%) और अन्य देशों का स्थान है। 2017 के दौरान इस क्षेत्र से परिवहन वाहनों का सबसे अधिक 12.6% निर्यात किया गया। खनिज ईंधन, तेल और संबंधित उत्पाद 12% के साथ दूसरे सबसे अधिक निर्यातित उत्पाद रहे। अन्य प्रमुख निर्यातित वस्तुओं में इलेक्ट्रिकल मशीनरी (9.1%), मशीनरी और उपकरण (8.5%), अयस्क, धातुमल (स्लैग) और भस्म (6.9%) शामिल रहीं।

लैक क्षेत्र में सबसे बड़ा आयातक भी मेक्सिको ही रहा, जिसने लैक क्षेत्र के कुल आयात का 41.5% अकेले ही आयात किया। 14.9% हिस्से के साथ ब्राजील दूसरा सबसे बड़ा आयातक रहा। इसके बाद अर्जेंटीना (6.6%), चिली (6.4%) और कोलंबिया (4.6%) तथा अन्य देशों का स्थान रहा। 2017 के दौरान, लैक क्षेत्र द्वारा 14.7% हिस्से के साथ इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरणों का सबसे अधिक आयात किया गया। इसके बाद मशीनरी और उपकरण (13.6%), खनिज ईंधन, तेल और इसके उत्पाद (11.8%), परिवहन वाहन (9.6%), प्लास्टिक और प्लास्टिक के उत्पाद (4.7%) का स्थान रहा।

चार्ट 1: लैक क्षेत्र के साथ भारत का व्यापार, 2008–17 (अरब यूएस डॉलर)

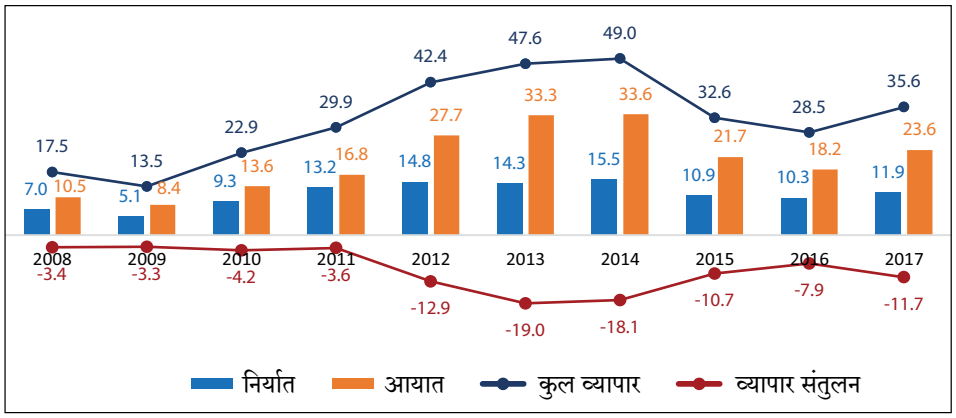

स्रोतः यूएन कॉमट्रेड से प्राप्त आईटीसी ट्रेड मैप और एक्ज़िम बैंक विश्लेषण

लैक क्षेत्र के साथ भारत के व्यापार संबंध

बीते दस वर्षों के दौरान, लैक क्षेत्र के साथ भारत का कुल व्यापार 2008 के 17.5 अरब यूएस डॉलर से बढ़कर 2017 में 35.6 अरब यूएस डॉलर हो गया। लैक क्षेत्र को भारतीय निर्यात 2008 के 7 अरब यूएस डॉलर से बढ़कर 2017 में 11.9 अरब यूएस डॉलर का हो गया। वहीं दूसरी ओर, लैक क्षेत्र से भारत के निर्यात में भी दोगुनी से अधिक वृद्धि हुई। यह 2008 के 10.5 अरब यूएस डॉलर से बढ़कर 2017 में 23.6 अरब यूएस डॉलर हो गया। **(चार्ट 1)**

लैटिन अमेरिका में अधिकांश भारतीय निर्यात मेक्सिको और ब्राजील में केंद्रित है, जो 2017 में भारत से लैक क्षेत्र को कुल निर्यात का क्रमशः 31% और 24.1% रहा। 80% से अधिक निर्यात छह देशों– मेक्सिको (31%), ब्राजील (24.1%), कोलंबिया (7.7%), चिली (6.2%), पेरू (6.1%) और अर्जेंटीना (5.5%) को ही रहा।

2017 में परिवहन वाहनों का निर्यात 30.8% रहा। भारत द्वारा लैक क्षेत्र को निर्यात किए जाने वाले अन्य प्रमुख उत्पादों में कार्बनिक रसायन, फार्मास्युटिकल उत्पाद, यांत्रिक उपकरण और विविध रासायनिक उत्पाद शामिल रहे, जिनका हिस्सा क्रमशः 7.6%, 6.1%, 5.5% और 5.1% रहा। इस क्षेत्र को भारत के कुल निर्यात का 55.1% हिस्सा इन्हीं पांच उत्पादों का रहा।

वर्ष 2017 में इस क्षेत्र से वेनेजुएला भारत का सबसे बड़ा आयातक रहा। इस क्षेत्र द्वारा कुल आयात का 25% अकेले वेनेजुएला ने ही आयात किया। इसके बाद 21.6% हिस्से के साथ ब्राजील का दूसरा स्थान रहा। इनके बाद, लैक क्षेत्र में भारत द्वारा आयात करने वाले अन्य प्रमुख देशों में 14.9% हिस्से के साथ मेक्सिको, 10.5% हिस्से के साथ अर्जेंटीना और 8.8% हिस्से के साथ पेरू शामिल रहे।

वर्ष 2017 में लैक द्वारा भारत से कुल आयातों का 2/5 से अधिक हिस्सा खनिज ईंधन और तेल उत्पादों की श्रेणी में रहा। इनके अतिरिक्त, 2017 में लैक क्षेत्र द्वारा भारत से आयातित कुछ अन्य प्रमुख उत्पादों में मोती और कीमती रत्न (13.6%), पशु तथा वनस्पति वसा (11.9%), अयस्क, धातुमल (स्लैग) और भस्म (11%), चीनी और मिष्ठान्न (4.4%) शामिल रहे।

लैक क्षेत्र के साथ भारत के इस व्यापार के बावजूद 2017 में लैक क्षेत्र के साथ भारत का व्यापार घाटा 11.7 अरब यूएस डॉलर हो गया। एक्ज़िम बैंक के 'भारत–लैक क्षेत्र व्यापारः हालिया रुझान और चुनिंदा देशों में अवसर' शीर्षक वाले हालिया शोध अध्ययन में बताया गया है कि लैक क्षेत्र में भारत का निर्यात बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं। इसके लिए इस शोध अध्ययन में मशीनरी और यांत्रिक उपकरण, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरण, प्लास्टिक और प्लास्टिक के उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद, ऑप्टिकल और फोटोग्राफिक उपकरण तथा अन्य उत्पादों को चिह्नित किया गया है।

क्षेत्रीय फोकस: मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका

मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका (मीना) क्षेत्र में 21 देश आते हैं। इनमें अल्जीरिया, बहरीन, जिबूती, मिस्र, ईरान, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मॉरिटानिया, मोरक्को, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, सीरिया, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब अमीरात, और यमन[1] शामिल हैं। ये देश 15 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले हैं। वैश्विक आबादी का 6.5% हिस्सा इन देशों में रहता है। विश्व के कुल कच्चे तेल भंडारों का दो-तिहाई हिस्सा इसी क्षेत्र में है। इनमें भी 1/5 से अधिक हिस्सा सऊदी अरब में ही है। ईरान विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार और चौथा सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार है। इस क्षेत्र में गैर-ईंधन खनिज और गैर-खनिज संसाधनों के भी विपुल भंडार हैं। दुनिया के फॉस्फेट उत्पादन का एक तिहाई हिस्सा अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, जॉर्डन और सीरिया में होता है। दुनिया के कुल फॉस्फेट फंडार का 30% अकेले मोरक्को में ही है।

मीना क्षेत्र का आर्थिक परिवेश

मीना क्षेत्र में 2017 में 4.1% की विकास दर आकलित की गई, जो 2016 की 12.3% दर से काफी कम रही। विकास दर में आई यह गिरावट मुख्य रूप से लगातार जारी भौगौलिक तनाव और तेल उत्पादन कम करने के चलते तेल निर्यातों में आई मंदी के कारण रही। 2016 में ईरान पर लगे प्रतिबंध हटे तो विकास दर ऊंची रही, लेकिन 2017 में इसमें कुछ गिरावट आई। इसका असर इस पूरे क्षेत्र की विकास दर पर पड़ा और इस क्षेत्रीय विकास दर में भी गिरावट आई। 2018 में इस क्षेत्र की विकास दर कुछ सुधार के साथ 4% रहने की उम्मीद है। मिस्र, लीबिया, सूडान और ईरान जैसे देशों में 2017 में मुद्रास्फीति काफी ज्यादा रही। वहीं दूसरी ओर, यमन, लेबनान और जॉर्डन में मुद्रा अवस्फीति की स्थिति रही। संयुक्त अरब अमीरात में चालू खाता सरप्लस रहा, जिससे क्षेत्र की बाहरी स्थिति में कुछ सुधार आया। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में इस क्षेत्र का चालू खाता घाटा 2016 के 4.6% की तुलना में घटकर 0.5% रह गया।

मीना क्षेत्र का अंतरराष्ट्रीय व्यापार

मीना क्षेत्र की संयुक्त आबादी 481 मिलियन है। 2017 में इसका जीडीपी 2.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर आंका गया था। इन दोनों तथ्यों के मद्देनजर यह क्षेत्र एक बड़ा बाजार है। मीना क्षेत्र का कुल व्यापार 2008 में 1.8 अरब यूएस डॉलर रहा था और 2017 में यह 1.9 अरब यूएस डॉलर रहा। यानी व्यापार में कमोबेश स्थिरता बनी हुई है। इस क्षेत्र से 2017 में निर्यात कुल वैश्विक निर्यात का 5.7% रहा और आयात वैश्विक आयात का 4.8% रहा। वैसे, मीना क्षेत्र के वैश्विक निर्यात में 2008 की तुलना में 2017 में कुछ गिरावट आई। 2008 में इस क्षेत्र से 1.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का निर्यात किया गया, वहीं 2017 में निर्यात का आंकड़ा 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर रहा। जबकि आयात में वृद्धि हुई। 2008 में इस क्षेत्र द्वारा 712.8 अरब यूएस डॉलर का आयात किया गया था, जो 2017 में बढ़कर 851.6 अरब यूएस डॉलर हो गया। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर निर्यातों और आयातों में वृद्धि हुई, जो 2016 के क्रमशः 867.9 अरब यूएस डॉलर और 827.7 अरब यूएस डॉलर से बढ़कर 2017 में क्रमशः 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर और 851.6 अरब यूएस डॉलर के रहे। तदनुसार, एक क्षेत्र के रूप में मीना का व्यापार सरप्लस 2008 के 418 अरब यूएस डॉलर की तुलना में 2017 में घटकर 150.2 अरब यूएस डॉलर रह गया।

वर्ष 2017 में मीना क्षेत्र के पांच सबसे बड़े निर्यातकों में संयुक्त अरब अमीरात (क्षेत्र के कुल निर्यातों का 30.8%), सऊदी अरब (22%), ईरान (10.6%), इराक (6.9%) और कतर (6.4%) शामिल रहे। इस क्षेत्र से अधिकांश निर्यात भारत, चीन, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण कोरिया को होता है। खनिज ईंधन, तेल और इनके स्रावण से बने उत्पाद इस क्षेत्र से निर्यात किए जाने वाली प्रमुख वस्तुएं हैं, जिनका हिस्सा 2017 में क्षेत्र से कुल निर्यातों का 57% रहा। 2017 में मीना क्षेत्र द्वारा निर्यातित अन्य प्रमुख वस्तुओं में मोती, कीमती रत्न और धातुएं, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरण, प्लास्टिक और प्लास्टिक की वस्तुएं, रेलवे और ट्रामवे से भिन्न वाहन, मशीनरी और यांत्रिक उपकरण शामिल रहे।

2017 में मीना क्षेत्र के पांच सबसे बड़े आयातकों में संयुक्त अरब अमीरात (इस क्षेत्र द्वारा कुल आयात का 31.7%), सऊदी अरब (14.9%), मिस्र (7.8%), ईरान (6.1%) और इराक (5.9%) शामिल रहे। आयात मुख्य रूप से चीन, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, भारत और तुर्की से किया गया। 2017 में प्रमुख आयातित माल में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (कुल आयातों का 12%), मशीनरी और यांत्रिक उपकरण (11.9%), मोती, कीमती रत्न और रेलवे तथा ट्रामवे से भिन्न वाहन (प्रत्येक 8.2%) तथा खनिज ईंधन (5.8%) शामिल रहे।

मीना क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)

अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2018 के अनुसार, 2017 में मीना क्षेत्र में एफडीआई में गिरावट आई। 2016 में 35.5 अरब यूएस डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2017 में घटकर 33.5 अरब यूएस डॉलर का रह गया। इस गिरावट का प्रमुख कारण रहा सऊदी अरब (दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक और मीना क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था) में एफडीआई में गिरावट आना। सऊदी अरब में एफडीआई गिरावट वहां मौजूद विदेशी कंपनियों के विनिवेश और ऋणों के चलते आई। मीना क्षेत्र के देशों में एफडीआई का असमान वितरण रहा। मीना क्षेत्र में 2017 में संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और ईरान सबसे ज्यादा एफडीआई आवक वाले देश रहे। इस क्षेत्र के कुल एफडीआई आवक का 68% हिस्सा इन्हीं देशों को रहा।

फायनेंशल टाइम्स के एफडीआई मार्केट्स डेटाबेस के अनुसार, 2008 से 2017 के दौरान मीना क्षेत्र में 10,052 परियोजनाओं में 810.7 अरब यूएस डॉलर का पूंजीगत निवेश रहा। इससे क्षेत्र में 14 लाख रोजगार पैदा हुए। इसी अवधि के दौरान कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस सबसे अधिक पूंजीगत निवेश प्राप्त करने वाला क्षेत्र रहा, जिसमें इस क्षेत्र के कुल निवेश का 25.8% हिस्सा निवेश किया गया। इसके बाद 23.8%, 11.6% और 7% हिस्से के साथ क्रमशः रियल एस्टेट, रसायन और होटल पर्यटन का स्थान रहा। 2008 से 2017 के दौरान मीना क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात सबसे बड़ा निवेशक रहा, जहां इस क्षेत्र को कुल निवेश का 15% निवेश किया गया। पिछले 10 वर्षों के दौरान अन्य प्रमुख निवेशकों में अमेरिका (मीना क्षेत्र को कुल एफडीआई आवक के 13.1% हिस्से के साथ), रूस और चीन (प्रत्येक 6.7%, फ्रांस (6.3%) और यूके (5.1%) का स्थान रहा।

[1] *वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक डेटाबेस, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष*

प्रस्तावना

हथकरघा उद्योग भारत के प्राचीनतम और सबसे बड़े कुटीर उद्योगों में से एक है, जो समृद्ध भारतीय संस्कृति का न सिर्फ प्रतिनिधित्व कर रहा है, बल्कि उसे संरक्षित भी कर रहा है। भारतीय शिल्पकारों को आज उनकी हाथ की बुनाई-कताई और सुंदर प्रिंटिंग के लिए दुनियाभर में जाना जाता है। मोटे तौर पर देखा जाए तो यह उद्योग घरों में चलता है और परिवार के सदस्य मिलकर उत्पादन करते हैं। देश के हजारों गांवो-कस्बों में ये कुटीर उद्योग चले आ रहे हैं और इन्हीं के साथ चला आ रहा है बरसों पुराना पारंपरिक कौशल, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिलते जाते हैं। हथकरघा उद्योग की मजबूती यही है कि इसमें बमुश्किल ही कोई बड़ी पूंजी लगी होती है। यह पर्यावरण स्नेही उद्योग है और इसमें बिजली की भी काफी कम खपत होती है। बाजार की जरूरतों के मुताबिक यह उद्योग नवाचार और बदलाव के लिए भी उपयुक्त है। मिसाल के तौर पर, देश के विभिन्न राज्यों में फैले हथकरघा उद्योग के कुछ उत्पाद हैं- जम्मू-कश्मीर के पश्मीना शॉल, तमिलनाडु की कांचीपुरम साड़ियां, गुजरात के कच्छ शॉल और असम का एरी और मुंगा सिल्क।

हथकरघा उद्योग को वर्तमान में कृषि के बाद भारत की सबसे बड़ी आर्थिक गतिविधि के रूप में देखा जाता है। इस उद्योग के जरिए बुनकर परिवारों में 30 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन हुआ है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने भी इस उद्योग के चहुंमुखी विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। तथापि, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आर्थिक उदारीकरण, तेजी से बढ़ते औद्योगीकरण, वैश्वीकरण और आधुनिक प्रौद्योगिकियों के साथ हथकरघा उद्योग के विकास के लिए चुनौतियां भी आई हैं।

उत्पादन

पिछले कुछ वर्षों से हथकरघा के इस्तेमाल से कपड़े का उत्पादन बढ़ रहा है। हथकरघा उद्योग द्वारा 2016-17 के दौरान कुल कपड़ा उत्पादन 8.01 अरब वर्ग मीटर रहा, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष 4.8% की वृद्धि दर्ज की गई। वैश्विक मंदी के चलते हथकरघा द्वारा कपड़ा उत्पादन में 2008-09 में गिरावट आई। हालांकि 2011-12 से हाथ से बुने कपड़ों का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। 2016-17 के दौरान कुल कपड़ा उत्पादन में हथकरघा उत्पादित कपड़ा 17.4% रहा।

व्यापार परिदृश्य

निर्यात

वर्ष 2017-18 में भारत हथकरघा उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक रहा। इनका निर्यात 353.9 मिलियन यूएस डॉलर का रहा। हालांकि दुनिया में हथकरघा उत्पादों की काफी मांग है, लेकिन भारत इस अंतरराष्ट्रीय बाजार में खुद को बेहतर तरीके से खड़ा नहीं कर पाया है। 2012-13 से 2017-18 के दौरान पिछले पांच वर्षों में हर साल इनके निर्यातों में गिरावट दर्ज की गई है। 2013-14 में हथकरघा उद्योग से 370.2 अरब यूएस डॉलर का निर्यात किया गया। इसमें 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान (-) 1.1% की ऋणात्मक सीएजीआर दर्ज की गई।

वर्ष 2017-18 में अमेरिका हथकरघा उत्पादों का सबसे बड़ा आयातक रहा था। हालांकि 2017-18 में निर्यातों में अमेरिका का हिस्सा घटकर 26.3% रह गया, जो 2013-14 में 32.0% था। 7.4% हिस्से के साथ यूके दूसरा सबसे बड़ा आयातक रहा, जिसे 26.1 मिलियन यूएस डॉलर का निर्यात किया गया। स्पेन भारतीय हथकरघा उत्पादों के तीसरे सबसे बड़े और महत्त्वपूर्ण आयातक के रूप में उभरा, जिसका हिस्सा 6.0% रहा। भारतीय हथकरघा के अन्य प्रमुख बाजारों में इटली (5.0%), जर्मनी (5.0%), संयुक्त अरब अमीरात (4.7%), फ्रांस (4.6%), नीदरलैंड (3.9%), ऑस्ट्रेलिया (3.3%) और जापान (3.3%) शामिल रहे।

अन्य टेक्सटाइल सामानों में कपड़ों के ऊपर से पहने जाने वाले वस्त्र (वोर्न क्लोदिंग) और वोर्न टेक्सटाइल भारत से सबसे अधिक निर्यातित खंड रहा, जिसका हिस्सा कुल हथकरघा निर्यात का 55.8% रहा। कालीन और गलीचे आदि दूसरा सबसे बड़ा निर्यातित खंड रहा। परिधान और क्लोदिंग एसेसरीज, बुनाई और क्रोशिया रहित कपड़े तीसरा सबसे बड़ा निर्यातित खंड रहा और कुल हथकरघा निर्यातों के 4.2% हिस्से के साथ इस खंड से 14.8 मिलियन यूएस डॉलर का निर्यात किया गया।

आयात

हथकरघा उत्पादों का आयात 2016-17 के 5.4 मिलियन यूएस डॉलर से दोगुना बढ़कर 2017-18 में 10.8 मिलियन यूएस डॉलर का रहा। हालांकि दीर्घावधि में देखा जाए तो आयातों में 12.9% की सीएजीआर से गिरावट दर्ज की गई और इनका आयात 2013-14 के 18.8 मिलियन यूएस डॉलर से घटकर 2017-18 में 10.8 मिलियन यूएस डॉलर का रह गया। भारत हथकरघा उत्पादों का सबसे अधिक आयात बांग्लादेश से करता रहा है। भारत के हथकरघा आयातों में बांग्लादेश का हिस्सा 2013-14 के 68.0% से बढ़कर 2017-18 में 88.3% हो गया। भारत को हथकरघा उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक चीन रहा, जिसका हिस्सा 2017-18 में 7.4% रहा। वर्ष 2017-18 में भारत हथकरघा उत्पादों के प्रमुख निर्यातकों में जापान, जर्मनी, यूके, ग्रीस, बेल्जियम, यूएस, सिंगापुर और इटली शामिल रहे।

हथकरघा क्षेत्र के विकास में कई बाधाएं भी हैं। जैसे- कच्चे माल की कमी, पावर लूम और मिल क्षेत्र से मिलने वाली प्रतिद्वंदिता, ऋण उपलब्धता का अभाव, संस्थागत अक्षमताएं, उद्योग की असंगठित प्रकृति, डिजाइनों में नयेपन का अभाव, अपर्याप्त अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, रंजकों (डाई) की कम गुणवत्ता, योजनाओं के बारे में जानकारी का अभाव और कुशल मानव संसाधनों का अभाव। विकास की इन बाधाओं को दूर करने के लिए कुछ रणनीतियां सुझाई गई हैं। जैसे- अच्छी गुणवत्ता वाला कच्चा माल सुलभ कराना, नए डिजाइनों का विकास, प्रभावी मार्केटिंग रणनीतियां अपनाना, ऋण सुलभ कराना, बाजार और उत्पादों का विशाखन और हथकरघा उद्योग का एक व्यापक डाटाबेस बनाना, जिसमें पिछले वर्षों के रुझान और उद्योग की विकास दर संबंधी आंकड़े हों।

पर्यटन क्षेत्र: रुझान और संभावनाएं

यात्रा और पर्यटन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। इसके कई कारण हैं। जैसे- प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सकारात्मक वृद्धि, बेहतर डिजिटल और भौतिक संपर्क और पर्यटन पर खर्च में बढ़ोत्तरी। दुनियाभर में कई पर्यटन स्थल उभरे हैं और पर्यटन क्षेत्र में निवेश भी बढ़ा है। आज सामाजिक-आर्थिक प्रगति में इस क्षेत्र का प्रमुख योगदान है। इस क्षेत्र में सबसे विशेषीकृत से लेकर अकुशल मानव संसाधनों तक के लिए अलग-अलग तरह के रोजगार पैदा करने की बड़ी क्षमता है। इस तरह चहुंमुखी विकास के लक्ष्य को हासिल करने में यह क्षेत्र अहम भूमिका निभा रहा है।

यात्रा और पर्यटन के वैश्विक आर्थिक प्रभाव पर विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद (डब्ल्यूटीटीसी) की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2017 में वैश्विक जीडीपी में इस क्षेत्र का योगदान 10.4 प्रतिशत और वैश्विक रोजगार में 9.9 प्रतिशत रहा। इस क्षेत्र से और भी कई अप्रत्यक्ष लाभ हुए। पर्यटन को बढ़ावा देने से सिर्फ नौकरियां की पैदा नहीं होतीं, बल्कि निर्यात भी बढ़ता है और दुनिया भर में समृद्धि के द्वार खुलते हैं। यह क्षेत्र दुनिया के बीच सांस्कृतिक पुल का भी काम करता है, जो वैश्विक शांति और एकता के लिए एक शक्तिशाली माध्यम हो सकता है। पर्यटन ऐसा क्षेत्र है, जिससे दूर-दराज के लोगों को अपनी संस्कृति, अपनी रिवाजों से दुनिया को परिचित कराने का मौका मिलता है। यह ऐसा क्षेत्र है जिसके जरिए कोई देश अपने समृद्ध नौसर्गिक और सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने लाने का अवसर मिलता है।

भारतीय पर्यटन क्षेत्र

भारत जैसे विकासशील देश में पर्यटन क्षेत्र का बड़ा महत्त्व है। एक तरफ यह क्षेत्र, भारत की समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक विविधता को सामने लाने के लिए एक बेहतरीन माध्यम है, तो वहीं दूसरी तरफ आर्थिक लाभ भी पहुंचाता है। रोजगार से लेकर निवेश और निर्यातों तक में पर्यटन क्षेत्र के योगदान को देखते हुए इस क्षेत्र के आर्थिक महत्त्व को भी समझा जा सकता है।

डब्ल्यूटीटीसी की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के जीडीपी में यात्रा और पर्यटन क्षेत्र का योगदान 15,239.6 अरब रुपए (लगभग 234.0 अरब यूएस डॉलर) रहा, जो जीडीपी का 9.4 प्रतिशत है। 2018 में भारत के जीडीपी में इस क्षेत्र का योगदान 7.5 प्रतिशत तक बढ़ने का पूर्वानुमान है। इसी प्रकार उम्मीद जताई जा रही है कि 2018-2028 के दौरान देश के जीडीपी में इस क्षेत्र का योगदान 6.9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ेगा। इस क्षेत्र के योगदान में इस वृद्धि के परिणामस्वरूप 2028 तक भारत के जीडीपी में यात्रा और पर्यटन क्षेत्र का योगदान बढ़कर 9.9 प्रतिशत हो जाने की उम्मीद है।

यात्रा और पर्यटन क्षेत्र देश में रोजगार भी पैदा करता है। 2017 में इस क्षेत्र में करीब 8 प्रतिशत रोजगारों का सृजन हुआ। 2028 तक इस क्षेत्र में रोजगारों की संख्या वर्तमान के 41.6 मिलियन से बढ़कर 52.3 मिलियन होने की उम्मीद है। 2017 में यात्रा और पर्यटन क्षेत्र से करीब 41.6 अरब यूएस डॉलर का पूंजीगत निवेश भी आया।

जनवरी 2003 से जून 2018 के दौरान भारतीय पर्यटन क्षेत्र में 15.07 अरब यूएस डॉलर का पूंजीगत विदेश निवेश भी आया। अमेरिका, यूके और फ्रांस क्रमशः 3.8 अरब यूएस डॉलर, 1.4 अरब यूएस डॉलर और 1.1 अरब यूएस डॉलर के निवेश के साथ प्रमुख निवेशकर्ता रहे।

आगंतुक निर्यात

बेशक पर्यटन एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है, पर कभी-कभी इस क्षेत्र को विदेशी मुद्रा आय के एक प्रमुख स्रोत के रूप में भी देखा जाता है। पर्यटक निर्यात से मतलब उस खर्च से है, जो विदेशी पर्यटक अपने व्यावसायिक तथा लीजर पर्यटन, दोनों तरह की यात्राओं के दौरान हमारे देश में आकर परिवहन आदि पर खर्च करते हैं। इसमें शिक्षा पर अंतरराष्ट्रीय खर्च शामिल नहीं किया जाता। डब्ल्यूटीटीसी के अनुसार, 2017 में आगंतुक निर्यात वैश्विक निर्यातों का 6.5 प्रतिशत रहा। इस वर्ष के दौरान भारत का आगंतुक निर्यात 27.3 अरब यूएस डॉलर रहा।

भारत में पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय में 2006-17 के दौरान 9.97 प्रतिशत की सीएजीआर दर्ज की गई और विदेशी पर्यटकों की अच्छी आवक रही। भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए शीर्ष 10 स्रोत बाजारों में अमेरिका, यूके, बांग्लादेश, श्रीलंका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, चीन, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया शामिल रहे। यानी इन देशों से सबसे अधिक विदेशी पर्यटक भारत आए। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल विदेशी पर्यटकों की पसंदीदा जगहें रहीं।

संभावनाएं

हाल में पर्यटन क्षेत्र में लगातार काफी विस्तार हुआ है और यह दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते और सबसे बड़े आर्थिक क्षेत्रों में से एक हो गया है। यूरोप और उत्तर अमेरिका में परंपरागत पर्यटन स्थलों के अतिरिक्त कई नए पर्यटन स्थल भी उभरे हैं। इस क्षेत्र में समय-समय पर लगने वाले झटकों के बावजूद बीतते समय के साथ अबाधित वृद्धि होती रही है। यह आर्थिक मंदी के दौर में इस क्षेत्र की मजबूती और लचीलेपन को दर्शाता है।

इतना ही नहीं, 2018-2028 के दौरान आगंतुक निर्यात वैश्विक स्तर पर 4.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ने का पूर्वानुमान है। इस तरह यह बढ़कर कुल निर्यातों का 6.9 प्रतिशत हो जाएगा। वर्ष 2028 तक भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़कर 30.47 मिलियन होने की उम्मीद है, जिससे करीब 50.9 अरब यूएस डॉलर की विदेशी मुद्रा आय का अनुमान है।

भारत के आगंतुक निर्यातों के लिए भारत में सकारात्मक संभावनाएं हैं। लेकिन इसके साथ ही पर्यटन में ही ऐसे अनछुए पहलू भी हैं, जिन्हें अच्छी गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे के जरिए भुनाया जा सकता है। पर्यटकों की सुरक्षा और सेहत के मामले विश्व जगत को आश्वस्त करना और प्रशिक्षित तथा कुशल मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना ऐसे ही पहलू हैं, जिन पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने लघु एवं मध्यम उद्यमों पर विशेष बल के साथ भावी बाजार प्रवेश व्यवस्था के रूप में ऋण-व्यवस्थाएं (एलओसी) प्रदान करने पर विशेष जोर दिया है। ये ऋण-व्यवस्थाएं भारतीय निर्यातक समुदाय को जोखिम और दायित्व रहित निर्यात वित्तपोषण का विकल्प प्रदान करती हैं, जो उन्हें नए बाजारों में पहुंच बढ़ाने और मौजूदा विदेशी बाजारों में निर्यात बढ़ाने में मदद करती हैं। एक्ज़िम बैंक विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों और अन्य विदेशी संस्थाओं को ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है, जो उन देशों के क्रेताओं को भारत से आस्थगित भुगतान शर्तों पर विकासपरक तथा बुनियादी संरचना परियोजनाओं, उपकरण, माल एवं सेवाओं का आयात करने में समर्थ बनाती हैं। एक्ज़िम बैंक भारत सरकार के आदेश पर भी ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है। इनके अंतर्गत एक्ज़िम बैंक माल के शिपमेंट पर भारतीय निर्यातक को संविदा मूल्य के 100 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करता है, बशर्ते कि कुल संविदा मूल्य के कम से कम 75 प्रतिशत के माल एवं सेवाओं का शिपमेंट भारत से किया गया हो। ऋण-व्यवस्थाओं के जरिए उभरते बाजारों में भारत की परियोजना निष्पादन क्षमता के प्रदर्शन में भी मदद मिली है।

हाल के वर्षों में ऋण-व्यवस्थाओं ने गति पकड़ी है। विशेष रूप से अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और सीआईएस क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की गई हैं।

बैंक द्वारा अब तक अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका ओशिनिया और सीआईएस क्षेत्रों के 62 देशों को 23.09 अरब यूएस डॉलर की ऋण प्रतिबद्धता के साथ 237 ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं, जो भारत से निर्यातों के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध हैं। इस प्रकार ऋण-व्यवस्थाएं विकासशील देशों में भारत से परियोजनाओं, माल और सेवाओं के निर्यात के संवर्द्धन और सुगमीकरण के लिए प्रभावी साधन हैं।

एक्ज़िम बैंक ने भारत सरकार के सहयोग से जुलाई-सितंबर, 2018 की अवधि के दौरान निम्नलिखित तीन ऋण-व्यवस्थाओं पर हस्ताक्षर किए:

(i) रवांडा सरकार को [क] दो विशेष आर्थिक जोन (एसईज़ेड) के विकास तथा किगाली विशेष आर्थिक ज़ोन (एसईज़ेड) के विस्तार एवं [ख] रवांडा में तीन कृषि परियोजनाओं के लिए 100-100 मिलियन यूएस डॉलर की दो ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की गईं। ये कृषि परियोजनाएं हैं- (i) वारुफु बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना, (ii) मुगेसेरा सिंचाई परियोजना और (iii) न्यामुकाना सिंचाई परियोजना। उक्त 200 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्थाओं सहित एक्ज़िम बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से रवांडा सरकार को अब तक 547.65 मिलियन यूएस डॉलर की 7 ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं। पूर्ववर्ती ऋण-व्यवस्थाएं रवांडा सरकार को बेस-ब्यूतेरो किदाहो सड़क परियोजना, न्याबोरंगो जलविद्युत परियोजना, निर्यात लक्षित आधुनिक सिंचाई कृषि परियोजना और 10 व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों और व्यवसाय केंद्रों की स्थापना के वित्तपोषण के लिए प्रदान की गई हैं।

(ii) सेनेगल सरकार को स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था के उन्नयन तथा पुनर्नवीकरण के लिए 24.50 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की गई। इस ऋण-व्यवस्था सहित सेनेगल को अब तक कुल 319.86 मिलियन यूएस डॉलर की 14 ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं। पूर्ववर्ती ऋण-व्यवस्थाएं सेनेगल सरकार को ग्रामीण विद्युतीकरण, मांस प्रसंस्करण, मत्स्य विकास,

आईटी प्रशिक्षण और सिंचाई आदि परियोजनाओं के लिए उपकरण तथा सेवाओं के भारत से निर्यातों के लिए प्रदान की गई हैं।

सफलता की कहानी: कैमरून

- एक्ज़िम बैंक ने कैमरून सरकार को 37.65 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की। यह ऋण-व्यवस्था मक्के और चावल की खेती संबंधी परियोजना में उपकरण आदि की आपूर्ति के लिए प्रदान की गई।
- उक्त ऋण-व्यवस्था के जरिए इबोलोवा ट्रैक्टर्स से संतोषजनक परिणाम देखने को मिले। 1000 ट्रैक्टरों में से 996 पहले ही असेंबल कर लिए गए और 870 ट्रैक्टरों को इस्तेमाल के लिए खेतों में उतारा जा चुका है।
- इस परियोजना के अंतर्गत मशीनरी, उपकरणों और ट्रैक्टरों की आपूर्ति से उत्पादन क्षमता बढ़ी। इस प्रकार, मक्के और चावल का उत्पादन बढ़ाने तथा उत्पादकता बढ़ाने में भी मदद मिली और इससे रोजगारों का सृजन भी हुआ।

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें :

श्री नदीम पंजेतन,
मुख्य महाप्रबंधक,
भारतीय निर्यात-आयात बैंक,
ऑफिस ब्लॉक, टावर 1, 7वीं मंजिल
रिंग रोड के पास, किदवई नगर (पूर्व)
नई दिल्ली - 110023
टेलीफोन: (011) 24607700
[ई-मेल : eximloc@eximbankindia.in]

एक्ज़िम बैंक ने की ईरा पुरस्कार 2017 के विजेता की घोषणा

डॉ. अमृता साहा को एक्ज़िम बैंक के अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध वार्षिक (ईरा) पुरस्कार 2017 का विजेता घोषित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनके शोध प्रबंध "भारतीय व्यापार नीति पर निबंध" के लिए दिया गया। इस पुरस्कार की घोषणा 09 अगस्त, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में एक्ज़िम बैंक के प्रबंध निदेशक श्री डेविड रस्कीना ने की। इस पुरस्कार के रूप में 3.50 लाख रुपए की राशि तथा प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाता है। डॉ. टी.सी.ए. अनंत, विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा भारत के पूर्व मुख्य सांख्यिकी एवं पूर्व सचिव, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार इस समारोह में विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉ. अमृता साहा के पुरस्कृत शोध प्रबंध पर आधारित एक्ज़िम बैंक के प्रासंगिक आलेख का भी विमोचन किया गया। इस अवसर पर डॉ. अमृता साहा के पुरस्कृरत शोध प्रबंध पर आधारित एक्ज़िम बैंक के प्रासंगिक आलेख का भी विमोचन किया गया। डॉ. अमृता साहा ने यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स, यूके से 2016 में डॉक्टोरल डिग्री हासिल की थी। उन्होंने अपनी थीसिस प्रोफेसर एल. ऐलन विंटर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स तथा प्रोफेसर इंगो बोर्शेर्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स के पर्यवेक्षण में लिखी है। डॉ. अमृता वर्तमान में इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स, यूके में पोस्ट डॉक्टेरल रिसर्चर हैं।

एक्ज़िम बैंक ने आईएनएसवी तारिणी के संपूर्ण महिला दल को किया सम्मानित

एक्ज़िम बैंक और नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय (एनएमएमएल) द्वारा संयुक्त रूप से रविवार, 12 अगस्त, 2018 को नई दिल्ली में आईएनएसवी तारिणी के संपूर्ण महिला दल के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आईएनएसवी तारिणी के इस छह सदस्यीय दल ने पिछले साल सितंबर के पहले सप्ताह में विश्वभ्रमण के लिए गोवा से एक यात्रा शुरू की थी, जो मई 2018 में समाप्त हुई। 254 दिनों की इस यात्रा के दौरान, इस दल ने लगभग 22,000 नॉटिकल मील की दूरी तय की और यह दल पांच देशों - ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, फ़ॉकलैंड द्वीप समूह (यूके), दक्षिण अफ्रीका और मॉरीशस से गुजरा। छह सदस्यीय दल में लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी (स्किपर), लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जामवाल, लेफ्टिनेंट कमांडर बी ऐश्वर्या, लेफ्टिनेंट कमांडर पी. स्वाति, लेफ्टिनेंट कमांडर विजया देवी और लेफ्टिनेंट पायल गुप्ता शामिल थीं। यह किसी भारतीय महिला दल द्वारा दुनिया का पहला सामुद्रिक विश्व भ्रमण है।

एक्ज़िम बैंक के प्रबंध निदेशक श्री डेविड रस्कीना ने कहा, "भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने वाले एक्ज़िम बैंक को इस साहसिक सामुद्रिक यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली अधिकारियों की टीम पर गर्व है। प्राचीन काल से ही भारत का व्यापार दुनिया भर में जलमार्गों और समुद्री मार्गों के जरिए हुआ है। नौकायन व्यापार का प्रमुख माध्यम रहा है। प्राचीन काल से, जहाजों के जरिए भारत से दूरदराज के देशों तक यात्रा की गई है। इन महिला अधिकारियों की उपलब्धि ने एक बार फिर यह साबित कर दिखाया है कि हमारे दृढ़संकल्पित युवाओं के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इन्होंने न सिर्फ दुनिया का भ्रमण किया है, बल्कि दुनिया में भारत का मान भी बढ़ाया है।"

एक्ज़िम बैंक ने अन्य ब्रिक्स देशों के विकास बैंकों के साथ मिलकर डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर / ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी पर अनुसंधान के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए

एक्ज़िम बैंक के प्रबंध निदेशक श्री डेविड रस्कीना ने ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) के सदस्य विकास बैंकों के अध्यक्षों के साथ एक बहुपक्षीय सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए। यह करार डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर / ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर मिलकर अनुसंधान करने पर सहमति स्वरूप किया गया है। यह सहयोग ज्ञापन ब्रिक्स देशों के सदस्य विकास बैंकों की वार्षिक बैठक में हुई चर्चा का परिणाम है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स अंतरबैंक सहयोग तंत्र के अंतर्गत सहयोग बढ़ाना है। इस अम्ब्रेला करार के अंतर्गत, हस्ताक्षरकर्ता विकास बैंकों ने एक संयुक्त अनुसंधान कार्यकारी समूह बनाने पर सहमति जताई है, जो अनुसंधान के एजेंडे और लक्षित परिणामों पर काम करेगा। यह कार्यकारी समूह वित्तीय क्षेत्र में और विशेष रूप से इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्तपोषण के क्षेत्र में डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर / ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के संभावित उपयोगों को चिह्नित करने की दिशा में भी शोध करेगा। डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर / ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पुरानी प्रक्रिया की जगह अपनाई जाने वाली एक अभिनव प्रक्रिया है, जो पेपरवर्क को कम करते हुए अत्यंत शीघ्रता से संव्यवहारों का निपटारा करने में सक्षम है। इस प्रकार इस करार के माध्यम से ब्रिक्स विकास बैंकों के बीच सहयोग बढ़ने तथा प्रक्रिया के सरल होने और इसमें तेजी आने की उम्मीद है। साथ ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए सीमापार भुगतान की लागत में भी कमी आएगी।

भारतीय एक्ज़िम बैंक ने की ब्रिक्स आर्थिक शोध पुरस्कार 2018 के विजेता की घोषणा

एक्ज़िम बैंक के आर्थिक शोध पुरस्कार 2018 की विजेता डॉ. ज़ेली ही रहीं। उन्हें यह पुरस्कार 'अंतरराष्ट्रीय व्यापार, कल्याण और असमानता पर आलेख' शीर्षक वाली उनकी डॉक्टोरल थीसिस के लिए दिया गया है। पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में आयोजित 8वीं वार्षिक ब्रिक्स वित्तीय फोरम के दौरान 25 जुलाई, 2018 को प्रदान किया गया। इसकी मेजबानी डेवलपमेंट बैंक ऑफ सदर्न अफ्रीका ने की। पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए (करीब 23,000 यूएस डॉलर), पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। विजेता को यह पुरस्कार डेवलपमेंट बैंक ऑफ सदर्न अफ्रीका के उपाध्यक्ष श्री फ्रांज़ बालेनी ने प्रदान किया। इस दौरान ब्रिक्स के सदस्य विकास बैंकों अर्थात ब्राजील के बीएनडीईएस; रूस के वेनेश्कोनॉम बैंक;और चाइना डेवलपमेंट बैंक के शीर्ष अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉ. ही की पुरस्कृत थीसिस पर आधारित एक्ज़िम बैंक के प्रासंगिक आलेख का भी विमोचन किया गया। डॉ. ज़ेली ही ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यूएसए से 2017 में अपनी डॉक्टोरल डिग्री हासिल की थी। वह फिलहाल पेन-वॉर्टन पब्लिक पॉलिसी इनिशिएटिव, यूएसए में अर्थशास्त्री के रूप में कार्यरत हैं।

चीन-अफ्रीका संबंधों का आधार लंबे समय से चला आ रहा पारस्परिक सहयोग रहा है। चीन अफ्रीका के आर्थिक विकास में निर्णायक भूमिका में बने रहने के हर संभव प्रयास कर रहा है। बदले में अफ्रीका ने चीन को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्राप्त करने और वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में एक अहम स्थिति प्राप्त करने के लिए सहयोग दिया है।

चीन-अफ्रीका भागीदारी के प्रमुख तत्वों में से एक है- चीन-अफ्रीका सहयोग फोरम (एफओसीएसी- फोकैक)। यह त्रैवार्षिक सम्मेलन है जिसकी शुरुआत समान विमर्श, सहमति बढ़ाने, सर्वसम्मति के विस्तार, प्रगाढ़ मैत्री तथा चीन और अफ्रीका में सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2000 में की गई थी। फोकैक सम्मेलनों के दौरान चीन द्वारा लगातार बढ़ती प्रतिबद्धताओं पर हाल के वर्षों में अंतरराष्ट्रीय जगत का ध्यान गया है। इन प्रतिबद्धताओं को अफ्रीका के साथ चीन के मजबूत होते संबंधों के रूप में देखा जा रहा है।

परंपरागत रूप से, चीन अपने फोकैक संकल्पों को दोगुना-तिगुना तक बढ़ा रहा है। 2006 में एक दशक से अधिक समय पहले तक चीन ने फोकैक सम्मेलन के दौरान 5 अरब यूएस डॉलर की वित्तीय प्रतिबद्धता जताई थी। इसमें अफ्रीका को 3 अरब यूएस डॉलर का रियायती ऋण और 2 अरब यूएस डॉलर का निर्यात ऋण शामिल था। फिर 2009 में चीन ने अपनी यह वित्तीय प्रतिबद्धता दोगुनी बढ़ाकर 10 अरब यूएस डॉलर कर दी। इसी तरह, 2012 में 20 अरब यूएस डॉलर और 2015 में 60 अरब यूएस डॉलर कर दी। हालांकि 2018 के फोकैक सम्मेलन में यह ट्रेंड टूटा और चीन इस तरह की बढ़ोत्तरी से बचा। 2015 और 2018 के वित्तीय संकल्पों को देखने से पता चलता है कि चीन ने अपनी रियायती दरों और अफ्रीका को वित्तपोषण की अपनी तरजीह के स्तर को भी कुछ कम किया है। **(चार्ट 1)**

एक तरफ अनुदानों की राशि, शून्य ब्याज दर वाले ऋण, रियायती ऋण और ऋण-व्यवस्थाएं 2015 के 40 अरब यूएस डॉलर की प्रतिबद्धता से गिरकर 2018 में 35 अरब यूएस डॉलर रह गए। निर्यात ऋणों के साथ संयुक्त किए गए रियायती ऋण 2015 में 35 अरब यूएस डॉलर के थे, जिन्हें अब 2018 में अनुदानों और शून्य ब्याज दरों वाले ऋणों की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। हालांकि इन तीनों (अनुदानों, शून्य ब्याज दर वाले ऋणों और रियायती ऋणों) का योग 15 अरब यूएस डॉलर होता है। तथापि, यह अनिश्चितता बनी हुई है कि मुफ्त अनुदान और शून्य ब्याज दर वाले ऋण मिलकर 2015 के स्तर (5 अरब यूएस डॉलर) से मेल खाएंगे। वहीं दूसरी तरफ, चीन अब भी 20 अरब यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्थाओं की प्रतिबद्धता जताता है, लेकिन अब यह ऋण निर्यात ऋण के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, जैसा कि 2015 में था। साथ ही ऐसे ऋणों का उल्लेख अब तरजीही ऋण के रूप में भी नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष चीन के संकल्प से 2015 का वह विशेष उल्लेख हटा दिया गया है, जिसमें रियायती ऋणों को और अधिक रियायती दरों पर उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई गई थी।

चार्ट 1: अफ्रीका को वित्तीय सहयोग का संकल्प - 2015 बनाम 2018

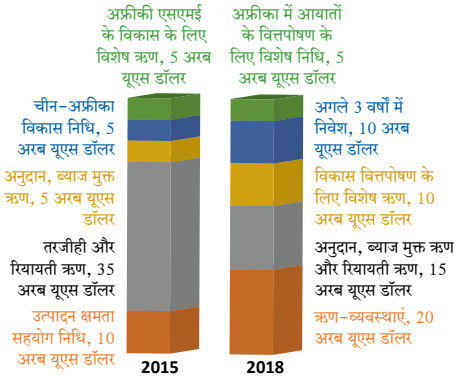

उधर, अफ्रीका में विकास वित्तपोषण के लिए 10 अरब यूएस डॉलर की विशेष निधि स्थापित करने और अफ्रीका में अगले तीन वर्षों में 10 अरब यूएस डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धताएं अफ्रीका में चीन के बदलते वित्तीय संबंधों को प्रदर्शित करती हैं। यह रुझान अफ्रीका में चीनी निवेशकों के विशाखन के चीन के इरादों को दिखाता है। अफ्रीका में चीनी सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक चीन की निजी कंपनियों को निवेश करने के लिए बढ़ाया जा रहा है। संभवतः चीन का इरादा चीनी विकास बैंक और चीन-अफ्रीका विकास कोष जैसी अपनी विकास वित्त संस्थाओं द्वारा प्रदत्त वित्तपोषण का उपयोग करने का है, ताकि अफ्रीका में चीनी कंपनियों के इक्विटी निवेश को सहयोग प्रदान किया जा सके।

हालांकि चीन के वित्तपोषण संकल्पों का दोगुना-तिगुना बढ़ते रहने की उम्मीद करना गलत होगा, लेकिन किसी भी तरह की वृद्धि में आने वाली रुकावट चीन के एहतियात बरतने वाले रुख को दर्शाती है। इन प्रतिबद्धताओं में आने वाली इस गिरावट का एक संभावित संकेत यह भी हो सकता है कि चीन अपने रिटर्न और अफ्रीका में वित्तपोषण की वाणिज्यिक व्यवहार्यता को लेकर चिंतित है। इसकी कुछ वजहें इस प्रकार हो सकती हैं- अफ्रीकी देशों के ऋण संकट के बढ़ते जोखिम को लेकर चिंताएं, बढ़ता चीनी पूंजी प्रवाह, चीन के फंसे हुए कर्ज का लगातार बढ़ते जाना, व्यापार युद्ध का चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ता प्रतिकूल प्रभाव और चीन द्वारा अपने विदेशी संबंधों में अपने करदाताओं का पैसा लगाने को लेकर घरेलू स्तर पर हो रही आलोचनाएं।

रणनीतिक दृष्टिकोण से, वैश्विक व्यापार में जारी अनिश्चितताओं और वैश्विक व्यापार पर वर्तमान अमेरिकी प्रशासन के पड़ते प्रभाव को देखते हुए, चीन को लगता है कि उसे अफ्रीका में व्यवसाय बढ़ाने के साथ-साथ इन व्यवसायों की व्यवहार्यता को लेकर एहतियात बरतते हुए अपने अंतरराष्ट्रीय व्यापार और राजनीतिक भागीदारियों में स्थिरता लाने के लिए अपने वैश्विक गठबंधनों में नए या मौजूदा संबंधों में सुधार पर विचार करना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों और बहुपक्षीय संस्थाओं द्वारा अफ्रीका की उधारियों और ऋण चुकौती क्षमता के आकलन और अफ्रीकी देशों को इन संस्थाओं से ऋण मिलने की कमतर संभावनाओं के बीच चीन का वित्तीय सहयोग अपने अफ्रीकी सहयोगी देशों को है, इसके बावजूद कि यह वृद्धिशील रूप से वाणिज्यिक शर्त पर है। हालांकि विकासशील देशों में बढ़ते चीनी वाणिज्यिक ऋणों और संभावित ऋण-जाल की चेतावनियों के चलते संप्रभुता पर जोखिम को लेकर चीनी ऋणों के आलोचकों का तर्क है कि चीन ने इस वर्ष अफ्रीका को अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं का भली-भांति मूल्यांकन कर लिया है। उनका कहना है कि चीन ने यह मूल्यांकन अफ्रीका को अपने वित्तपोषण की वाणिज्यिक व्यवहार्यता और इस वर्ष की फोकैक प्रतिबद्धताओं की घोषणा करने से पहले अपनी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले इसके भार को ध्यान में रखकर किया है।

एक्ज़िम बाज़ार- हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की एक अनूठी प्रदर्शनी और शोध अध्ययन का विमोचन

एक्ज़िम बैंक भारत की परंपरागत कला और शिल्प को सहेजने और शिल्पकारों को नियमित आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के दोहरे उद्देश्य से देशभर के ग्रासरूट उद्यमों और शिल्पकारों को उत्पाद एवं डिजाइन विकास तथा पैकेजिंग के लिए सहयोग प्रदान करता रहा है। बैंक ने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के जरिए नई पीढ़ी के शिल्पकारों को अपनी परंपरागत शिल्प कलाओं को सीखने और व्यवसाय का मॉडल खड़ा करने के लिए प्रेरित करते हुए विभिन्न शिल्प कलाओं को भारत तथा विदेशों के अनेक बाजारों में स्थापित करने में उनका सहयोग किया है। अपने इन प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए एक्ज़िम बैंक ने इस वर्ष 'एक्ज़िम बाज़ार' का आयोजन किया। यह तीन दिवसीय कार्यक्रम 28 से 30 सितंबर, 2018 तक मुंबई के वर्ली स्थित नेहरू सेंटर में आयोजित किया गया। यह एक्ज़िम बाज़ार का दूसरा संस्करण था।

इस प्रदर्शनी में 62 से ज्यादा शिल्पकार अपने हाथ का हुनर लेकर आए। प्रदर्शनी में आंध्रप्रदेश, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल सहित 25 से अधिक राज्यों के शिल्पकार समूहों ने हिस्सा लिया और अपने उत्पादों की बिक्री की। प्रदर्शनी के दौरान कश्मीरी कढ़ाई वाले कपड़ों और हाथ से बुने पश्मीना शॉल से लेकर ढोकरा शिल्प वस्तुएं, सांझी पेंटिंग, टेराकोटा और ब्लैक पॉटरी वस्तुएं, चेन्नापटना के खिलौने, मिनिएचर, फड़ और पिछवाई चित्रकारी, एप्लीक और कढ़ाई किए हुए कपड़े, जूट के बैग और चटाइयां, पंजाबी जूतियां, जूते-चप्पल, वारंगल के कालीन, इकत टेक्सटाइल्स, ऑर्गेनिक शहद, चमड़े की कठपुतलियां, हाथ और पैरों से की गई चित्रकारी, घास से बुनी टोकरियां, सेरामिक बर्तन, मधुबनी और पट्टचित्र चित्रकारी आदि की बिक्री हुई। इस तीन दिवसीय आयोजन में 2000 से अधिक लोग आए। प्रदर्शनी के दौरान करीब 33 लाख रुपए की हाथों-हाथ बिक्री हुई और शिल्पकारों को करीब 13 लाख रुपए के ऑर्डर मिले।

एक्ज़िम बाज़ार के उद्घाटन के अवसर पर बैंक के शोध अध्ययन भारतीय हथकरघा उद्योगः संभावनाएं और परिप्रेक्ष्य का भी विमोचन किया गया। इस शोध अध्ययन में हथकरघा उत्पादों की इस खासियत पर जोर दिया गया है कि ये पर्यावरण अनुकूल (ईको-फ्रेंडली) और ऑर्गेनिक होते हैं और यह ऐसी खासियत है, जिसे ग्राहकों का ध्यान खींचने के लिए भुनाये जाने की जरूरत है।

एक्ज़िम बैंक अपनी मार्केटिंग सलाहकारी सेवाओं के माध्यम से, भारतीय कंपनियों की निर्यात क्षमताओं और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए एक संवर्धक की भूमिका निभाता है। बैंक निर्यातकों के लिए विदेशों में अवसरों की पहचान करने और उनके उत्पादों और सेवाओं के लिए विदेशी वितरकों/ खरीदारों/ भागीदारों का पता लगाने में सक्रिय रूप से सहायता कर भारतीय निर्यातक कंपनियों के वैश्वीकरण प्रयासों में उनकी मदद करता है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया लिखिएः mas@eximbankindia.in पर।

एक्ज़िमिअस शिक्षण केंद्र की गतिविधियां

एक्ज़िम बैंक ने भारतीय निर्यातकों के संगठन फिओ के साथ मिलकर 6 जुलाई, 2018 को जयपुर में 'राजस्थान से निर्यातों की संभावनाएं' विषय पर सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार में राजस्थान के उद्योग मंत्रालय, राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) और एक्ज़िम बैंक के वक्ता रहे। उन्होंने टेक्सटाइल्स, हस्तशिल्प, रत्न एवं आभूषण, कृषि उत्पादों और मार्बल जैसे क्षेत्रों से राजस्थान के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निर्यातकों को विभिन्न जानकारियां दीं।

एक्ज़िम बैंक ने विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मिलकर 7 अगस्त, 2018 को 'ऋण-व्यवस्थाओं के अंतर्गत सौर परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 'बिजनेस आउटरीच कार्यक्रम' का आयोजन किया। कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली स्थित प्रवासी भारतीय केंद्र में किया गया। कार्यक्रम को विदेश मंत्रालय, विद्युत और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, एक्ज़िम बैंक तथा सौर ऊर्जा क्षेत्र की चुनिंदा भारतीय कंपनियों के अधिकारियों ने संबोधित किया। कार्यक्रम के बाद एक चर्चापरक सत्र का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य देशों के मिशनों के प्रमुख भी उपस्थित रहे।

एक्ज़िम बैंक ने इंडो ग्लोबल एसएमई चैंबर के साथ मिलकर इंदौर में 13 अगस्त, 2018 को 'मध्य प्रदेश से निर्यात रणनीति' विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार में मध्य प्रदेश के करीब 100 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निर्यातकों ने हिस्सा लिया। ये निर्यातक टेक्सटाइल, फार्मा उत्पादों, लाइट इंजीनियरिंग, खाद्य उत्पादों और रेडीमेड कपड़ों जैसे क्षेत्रों से थे। सेमिनार में मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों सहित ईसीजीसी लिमिटेड, डीजीएफटी, मध्य प्रदेश और लघु उद्योग संगठन तथा एक्ज़िम बैंक के अधिकारी वक्ता के रूप में उपस्थित रहे।

एक्ज़िम बैंक ने इस तिमाही के दौरान संशोधित निर्यात-आयात नीति 2018 (कोलकाता), एक्ट ईस्ट बिजनेस शो (शिलॉन्ग), एमएसएमई सम्मेलन (पानीपत) और एसएमई विनिर्माता तथा निर्यात सम्मेलन (पुणे) में सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन करने के लिए अन्य व्यापार संघों के साथ साझेदारी की।

अपने क्षेत्र में एक्ज़िम बैंक के आगामी कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए देखिएः www.eximbankindia.in/upcomingevents.

एक्ज़िम बैंक के एक्सपोर्ट लीडिंग इंडेक्स के अनुसार भारत के निर्यातों का पूर्वानुमान

एक्ज़िम बैंक ने अपने आंतरिक एक्सपोर्ट लीडिंग इंडेक्स मॉडल के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018-19 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई-सितंबर 2018 के दौरान, पिछले वर्ष की इसी तिमाही के मुकाबले भारत के कुल वस्तु निर्यातों में 12.3 प्रतिशत तथा गैर-तेल निर्यातों में 12.4 प्रतिशत की वृद्धि होने का पूर्वानुमान लगाया है। यह पूर्वानुमान एक्ज़िम बैंक के एक्सपोर्ट लीडिंग इंडेक्स (ईएलआई) मॉडल पर आधारित है, जिसमें निरंतर सकारात्मक वृद्धि दिखाई देती है। भारत के कुल वस्तु निर्यातों और गैर-तेल निर्यातों में वृद्धि का पूर्वानुमान हर तिमाही आधार पर संबंधित तिमाही के लिए जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च के पहले सप्ताह में जारी किया जाता रहेगा और इस मॉडल में भी निरंतर सुधार का प्रयास किया जाता रहेगा। अक्टूबर-दिसंबर 2018 तिमाही के लिए भारत के निर्यातों में वृद्धि का पूर्वानुमान दिसंबर 2018 के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा।

इस मॉडल तथा इससे प्राप्त पूर्वानुमान संबंधी परिणामों की समीक्षा विशेषज्ञों की एक स्थाई तकनीकी समिति द्वारा की गई है। इस समिति के सदस्यों में प्रोफेसर सैकत सिन्हा रॉय, प्रोफेसर एवं संयोजक, सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज, अर्थशास्त्र विभाग, जाधवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता; डॉ. सरत धल, निदेशक, अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता; प्रोफेसर एन.आर. भानुमूर्ति, प्रोफेसर, नेशनल इंडस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फायनेंस एंड पॉलिसी (एन आई पी एफ पी), नई दिल्ली तथा प्रोफेसर सी. वीरामणि, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च (आई जी आई डी आर), मुंबई शामिल हैं।

एक्ज़िम बैंक द्वारा अपने निरंतर शोध प्रयासों की कड़ी में भारत के निर्यातों का तिमाही आधार पर ट्रैक रखने तथा वृद्धि में पूर्वानुमान के लिए एक्सपोर्ट लीडिंग इंडेक्स (ई एल आई) तैयार करने हेतु यह इन-हाउस मॉडल विकसित किया गया है। इस इंडेक्स को देश के निर्यातों पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न बाह्य एवं घरेलू कारकों को ध्यान में रखते हुए इस मॉडल को देश के वस्तु निर्यातों में तिमाही आधार पर वृद्धि का पूर्वानुमान लगाने के लिए एक प्रमुख संकेतक के रूप में विकसित किया गया है।

किर्गिस्तान

किर्गिस्तान का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) व्यक्तिगत खपत और निवेश के चलते 2017 में 4.6 प्रतिशत की दर से बढ़ा। जीडीपी पर कुमटोर स्वर्ण खान के उत्पादन और निर्यातों का काफी असर रहा। स्वर्ण उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कम रहने के चलते 2018 में वास्तविक जीडीपी के औसत 3.8 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। इसलिए किर्गिस्तान की अर्थव्यवस्था मुख्यतः निर्यातों और अचल आस्तियों पर आधारित है। उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर वैश्विक वस्तु कीमतों में बढ़ोत्तरी के चलते 2016 के 0.4 प्रतिशत से बढ़कर 3.2 प्रतिशत हो गई। रूबल में उतार-चढ़ाव किर्गिस्तान की मुद्रा सोम के लिए महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि रूस किर्गिस्तान का अग्रणी व्यापार भागीदार देश है और अर्थव्यवस्था में रेमिटैंस का प्रवाह बनाए रखने के लिए अहम है। 2016 और 2017 में रूबल में स्थिरता के चलते सोम मजबूत हुआ था और 2017 में 1 यूएस डॉलर के मुकाबले सोम का मूल्य 69 था। 2018 में निर्यातों में अच्छी वृद्धि और रेमिटैंस में बढ़ोत्तरी के चलते यूएस डॉलर के मुकाबले सोम के और मजबूत होने के आसार हैं। हालांकि आयातों की मांग बढ़ने के कारण देश का चालू खाता घाटा 2017 में जीडीपी के 4.6 प्रतिशत से थोड़ा-सा बढ़कर 2018 में जीडीपी का 4.8 प्रतिशत हो सकता है। तथापि, रेमिटैंस में बढ़ोत्तरी का सीधा प्रभाव चालू खाता घाटा को कम करने में मदद भी कर सकता है।

अर्जेंटीना

अंर्जेंटीना पर छाए मंदी के बादल अभी छंटने की उम्मीद बहुत कम है। मंदी के चलते देश की जीडीपी विकास दर भी 2017 के 2.9 प्रतिशत से घटकर 2018 में 2.2 प्रतिशत रहने की आशंका है। अर्जेंटीना की मुद्रा में तेजी से आती गिरावट और राजकोषीय व्यय का कम होना इसके प्रमुख कारण हैं। हालांकि इस गिरावट का प्रारंभिक कारण भयंकर सूखा पड़ना रहा। लेकिन उपभोक्ता और व्यापारी वर्ग का भरोसा टूटने के कारण हालात और बिगड़ गए। 2018 में सार्वजनिक व्यय और अधिक सिकुड़ने और ब्याज दरें बढ़ने के चलते ऋण की मांग में भी कमी आने के आसार हैं। मुद्रा में आई हालिया गिरावट के कारण उपभोक्ता मूल्य भी बढ़ सकते हैं और बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी के राजकोषीय भार को कम करने की जरूरत के चलते महंगाई और अधिक बढ़ेगी। उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर 2017 के 26.5 प्रतिशत से बढ़कर 2018 में बढ़कर 32.9 प्रतिशत होने के आसार हैं। अर्जेंटीना की मुद्रा पेसो में 2018 में और अधिक गिरावट आने की आशंका है। अगस्त 2018 में पेसो में आई बड़ी गिरावट के कारण पेसो का अवमूल्यन हुआ। चालू खाता घाटा 2016 में जीडीपी के 2.7 प्रतिशत से बढ़कर 2017 में जीडीपी का 4.9 प्रतिशत हो गया। हालांकि अगस्त में पेसो में आई गिरावट का एक असर यह भी हुआ कि हाल के वर्षों में इस मुद्रा का संचयी अधिमूल्यन रिवर्स हो गया और इस बाहरी प्रतिस्पर्धात्मकता से चालू खाता घाटे के समायोजन में मदद मिलेगी, जिसके 2018 में घटकर जीडीपी का 4.4 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

मालदीव

मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटन और मत्स्यपालन पर निर्भर है। यहां की वास्तविक जीडीपी 2017 में 4.6 प्रतिशत की दर से बढ़ी, जो इससे पिछले वर्ष 3.9 प्रतिशत रही थी। विकास दर में यह बढ़ोत्तरी पर्यटन क्षेत्र में सुधार और निर्माण क्षेत्र में आई मजबूती के कारण देखी गई। औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर 2016 के 0.8 प्रतिशत से बढ़कर 2017 में 2.5 प्रतिशत हो गई। अक्टूबर 2016 में किए गए खाद्य और बिजली सब्सिडी संबंधी सुधार और मार्च 2017 में सिगरेट, सॉफ्ट और एनर्जी ड्रिंक्स पर आयात शुल्क बढ़ाना इसके प्रमुख कारण रहे। मालदीव में बड़े स्तर पर बुनियादी विस्तार हो रहा है। सरकार ने लोगों को छोटे द्वीप से एक बड़े माले क्षेत्र में लाने के लिए कई बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं शुरू की हैं। इसके अतिरिक्त, बुनियादी ढांचागत सुविधाएं बढ़ने से पर्यटन क्षेत्र के भी और बढ़ने की उम्मीद है। 2018 में वास्तविक जीडीपी विकास दर 4.7 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। औसत उपभोक्ता मूल्य आधारित मुद्रास्फीति 2017 की 2.5 प्रतिशत के मुकाबले 2018 में 2.1 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, जो वस्तु मूल्यों और आर्थिक निष्पादन में स्थिरता को प्रदर्शित करती है। मालदीव में बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के विकास के लिए आयात बढ़ने से देश का चालू खाता घाटा भी 2017 के 779 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 818 मिलियन यूएस डॉलर होने के आसार हैं।

जिम्बाब्वे

जिम्बाब्वे की अर्थव्यवस्था 2012 के बाद से लगातार बढ़ रही है। देश की आर्थिक वृद्धि दर 2016 के 0.7 प्रतिशत से बढ़कर 2017 में 2.4 प्रतिशत रही। यह बढ़ोत्तरी कृषि के लिए उपयुक्त मौसम और उर्वरकों के आयातों से शुल्क हटाने के चलते रही। उपभोक्ता मूल्य आधारित मुद्रास्फीति 2016 के 1.5 प्रतिशत मुद्रा अवस्फीति की तुलना में 2017 में वैश्विक स्तर पर वस्तुओं के मूल्य में बढ़ोत्तरी के चलते 0.8 प्रतिशत के सकारात्मक स्तर पर रही। वास्तविक जीडीपी 2018 में 2.0 प्रतिशत रही, जो सरकार के 4.5 प्रतिशत के अनुमान से काफी कम रही। उपभोक्ता मूल्यों में औसतन वृद्धि 2017 के 0.9 प्रतिशत की तुलना में 2018 में 3.5 प्रतिशत होने की उम्मीद है। इसका प्रमुख कारण अंतरराष्ट्रीय खाद्य और पेय पदार्थों तथा तेल की वैश्विक कीमतों में बढ़ोत्तरी होना है। 2016 की दूसरी छमाही में जिम्बाब्वे सरकार ने बॉन्ड नोटों की पहली किस्त जारी की। यूएस डॉलर के समतुल्य मूल्य वाले ये नोट स्थनीय मुद्रा हैं, जिन्हें अर्थव्यवस्था में नकदी की कमी को पूरा करने के लिए जारी किया जा रहा है। इन्हें मौजूदा विदेशी मुद्रा नोटों अधिकांशतः यूएस डॉलर, तथा रैंड, यूरो, पाउंड और बोत्सवाना पुला जैसी छोटी विदेशी मुद्राओं की अपर्याप्त आपूर्ति को पूरा करने के लिए जारी किया जा रहा है। इसकी विनिमय दर 2018 में 1 यूएस डॉलर के मुकाबले 1 जिम्बाब्वे डॉलर रहने की उम्मीद है, जो 2017 में भी यही थी। देश का चालू खाता घाटा 2017 में जीडीपी के 3.6 प्रतिशत से बढ़कर 2018 में जीडीपी का 6.9 प्रतिशत हो जाने के आसार हैं।

अर्जेंटीना पेसो

अर्जेंटीना पेसो में सितंबर के आखिरी दिन पेसो में 4.7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और इसका मूल्य एक यूएस डॉलर के मुकाबले 41.15 पेसो रहा। यह गिरावट नए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष डील के अंतर्गत घोषित मौद्रिक नीति में बदलावों के मद्देनजर यूएस मुद्रा खरीद में अच्छी रुचि के बावजूद देखी गई।

अर्जेंटीना ने आईएमएफ के साथ 57 अरब यूएस डॉलर के वित्तपोषण सौदे की घोषणा की। इस घोषणा से कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्रीय बैंक के उपायों के बिना ही एक यूएस डॉलर के मुकाबले पेसो का मूल्य 34 से 44 के बीच बना रहेगा। इस डील का उद्देश्य मौद्रिक आधार में तीव्र वृद्धि को रोकना भी है।

इस वर्ष यूएस डॉलर के मुकाबले 50 प्रतिशत से अधिक अवमूल्यित हो चुका पेसो अगस्त में एक यूएस डॉलर के मुकाबले 41.36 के सबसे निचले स्तर तक पहुंच गया था।

पेसो में यह तीव्र गिरावट आईएमएफ की ओर से दिए जाने वाले बेल आउट पैकेज में अतिरिक्त 7.1 अरब यूएस डॉलर बढ़ाने की सहमति के बावजूद आई। इससे बेलआउट पैकेज 57.1 अरब यूएस डॉलर का हो गया, जो इस बहुपक्षीय संस्था का अब तक का सबसे बड़ा ऋण रहा। संशोधित करार के अनुसार, आईएमएफ ने अभी से 2019 के बीच की अवधि के दौरान इसमें से अधिकतम निधि का इस्तेमाल करने की अनुमति भी दे दी। इससे देश द्वारा जिन जोखिमों का सामना किया जा रहा है, वे कुछ कम हो जाते हैं।

तथापि, बड़ा सवाल यह है कि मितव्ययिता पर आईएमएफ के कार्यक्रम का फोकस अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था को किस तरह प्रभावित करता है, जिसमें इस वर्ष 2 प्रतिशत से अधिक की गिरावट होने का पूर्वानुमान है। इस वर्ष ब्याज दरों के 60 प्रतिशत और मुद्रास्फीति दर के 40 प्रतिशत से अधिक की क्रूरतम बढ़ोत्तरी की आशंका है। राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री द्वारा आईएमएफ के मितव्ययता कार्यक्रम को अपना लेने पर सामाजिक अशांति बढ़ेगी और अगले साल के चुनाव में उन्हें इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।

तुर्किश लीरा

लीरा इस वर्ष यूएस डॉलर के मुकाबले करीब 40 प्रतिशत गिर चुका है। इस गिरावट के मुख्य कारण राष्ट्रपति तैयप इरोडगन का मौद्रिक नीति से ढीला होता नियंत्रण और तुर्की तथा अमेरिका के बीच राजनयिक विवाद रहे। अगस्त में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पादरी एंड्रू ब्रुन्सन पर लगे आतंकवाद के आरोपों के बाद तुर्की से आयातों पर अतिरिक्त शुल्क लगा दिए थे।

अंकारा और वाशिंगटन के बीच पैदा हुए इस विवाद के चलते तुर्किश लीरा अगस्त में डॉलर के मुकाबले 7.24 प्रतिशत गिरा। इसके बाद तुर्की ने अपनी मुद्रा को संभालने के लिए कई उपाय किए। केंद्रीय बैंक ने दरों में 6.25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की और सरकार द्वारा एक नए आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की गई।

लेकिन कमजोर लीरा के साथ-साथ दोहरे अंकों वाली मुद्रास्फीति दर और मुख्य ब्याज दर 24 प्रतिशत रही, जिसके चलते तुर्की की अर्थव्यवस्था में वर्ष की दूसरी छमाही में भी मंदी बरकरार रही।

वित्त मंत्री बेरात अल्ब्रायक द्वारा प्रस्तुत किए गए नए आर्थिक कार्यक्रम में भी 2018 और 2019 के लिए विकास दर के निम्न रहने का ही पूर्वानुमान जाहिर किया गया है। आर्थिक और विनिर्माण गतिविधियों में भरोसे पर आए नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि दोनों ही मोर्चों पर 2009 के बाद से यह सबसे बड़ी गिरावट है।

निवेशक बैंकिंग जगत की स्थिति को लेकर भी चिंतित हैं। बैंकिंग जगत बड़े पैमाने पर फंसे हुए कर्ज का सामना कर रहा है। लीरा में बढ़ती गिरावट के साथ-साथ कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा ऋण चुकौती भी घटती जा रही है।

वेनेजुएला बोलिवर

आर्थिक उथल-पुथल के बीच वेनेजुएला बोलिवर में कुछ स्थिरता आई है। शुरुआती गिरावट के बाद पहले छह हफ्तों में सरकार द्वारा मुद्रा के अवमूल्यन और पुनर्मूल्य वर्गीकरण करने बाद ब्लैक मार्केट में इसमें सिर्फ 19 प्रतिशत की गिरावट आई। हालांकि यह कतई जरूरी नहीं कि इससे विदेशी मुद्रा विनिमय में भी स्थिरता आए, लेकिन ऐसी स्थिति में जहां मुद्रास्फीति दर के लगातार बेलगाम बने रहने के कारण अर्थव्यवस्था को जो नुकसान पहुंचा है, वहां यह स्थिरता बीते कुछ समय के दौरान पहली सामान्य घटना है।

बोलिवर में देखी गई यह तुलनात्मक स्थिरता भी वेनेजुएला के लिए बहुत अधिक लाभदायक साबित होगी, ऐसा कहना मुश्किल है। बल्कि कहा तो यहां तक जा रहा है कि बेलगाम मुद्रास्फीति दर की खतरनाक रफ्तार को कुछ धीमा करने में भी शायद ही कुछ मदद मिले, जिसके इस वर्ष 1 मिलियन प्रतिशत पहुंचने का पूर्वानुमान है। राष्ट्रपति निकोलस माडुरो ने पिछले महीने बोलिवर में 95 प्रतिशत का अवमूल्यन किया, जिसे देशभर में फैले ब्लैक मार्केट विनिमय की मौन स्वीकृति के रूप में देखा जा रहा है।

अपनी नई आर्थिक योजना के अनुसार, माडुरो ने देश की आधिकारिक डॉलर नीलामियों की आवृत्ति भी सप्ताह में एक से बढ़ाकर तीन कर दी है, जिसे डायकॉम के नाम से जाना जाता है।

विभिन्न दरों के आकलन करने वाले मॉनिटर डॉलर के आंकड़ों के अनुसार, आधिकारिक रूप से मुद्रा के अवमूल्यन के तुरंत बाद ब्लैक मार्केट दरों में शुरुआती गिरावट के बाद समानांतर दर इस वर्ष की तुलनात्मक स्थिरता के माह की शुरुआत से ही 100 से 116 बोलिवर के बीच बनी रही। बोलिवर अगस्त में 63 प्रतिशत की तुलना में इस महीने 14 प्रतिशत ही गिरा।

बहुत संभव है कि ब्लैक मार्केट अवमूल्यन में आई यह स्थिरता दीर्घकालिक न हो, क्योंकि वेनेजुएला के लोगों के लिए डायकॉम सिस्टम को एक्सिस करना अब भी मुश्किल बना हुआ है और एक साल में 2000 यूएस डॉलर खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत सीमित है। इस बीच, ब्लूमबर्ग के कैफे कॉन लेशे इंडेक्स के अनुसार, सरकार लगातार नोट छाप रही है और वार्षिक मुद्रास्फीति करीब 111,000 प्रतिशत के आसपास चल रही है।

वस्तु व्यापार

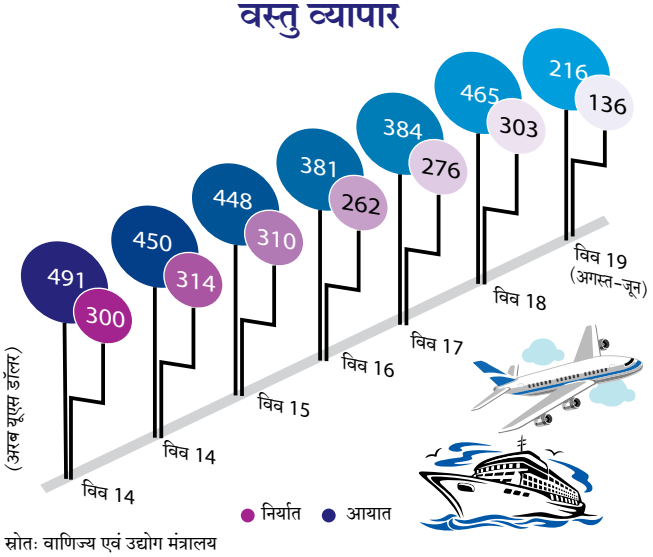

स्रोतः वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

सेवा व्यापार

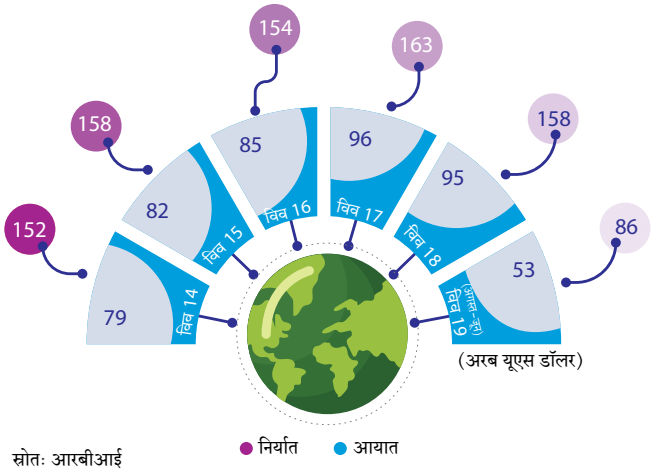

स्रोतः आरबीआई

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह

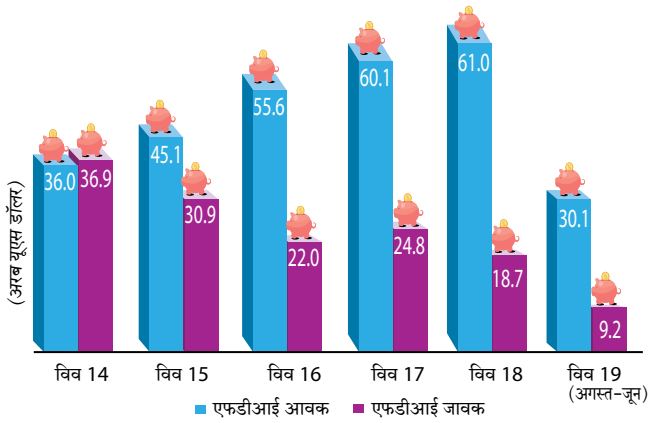

स्रोतः औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग और आरबीआई

उपभोक्ता मूल्य आधारित मुद्रास्फीति (सीपीआई)

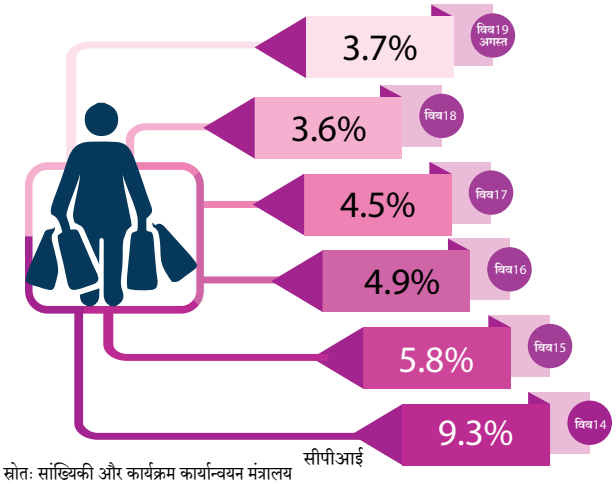

स्रोतः सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

चालू खाता शेष

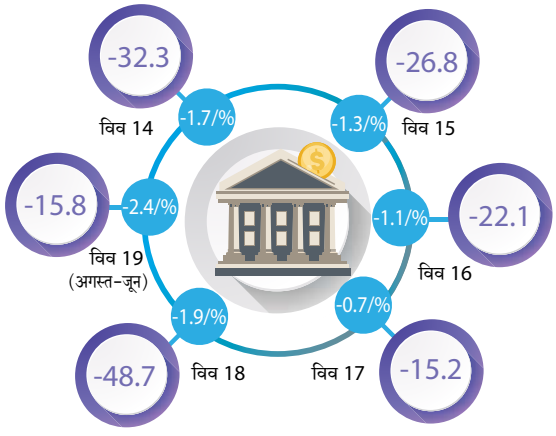

स्रोतः आरबीआई

क्षेत्रवार उत्पादन

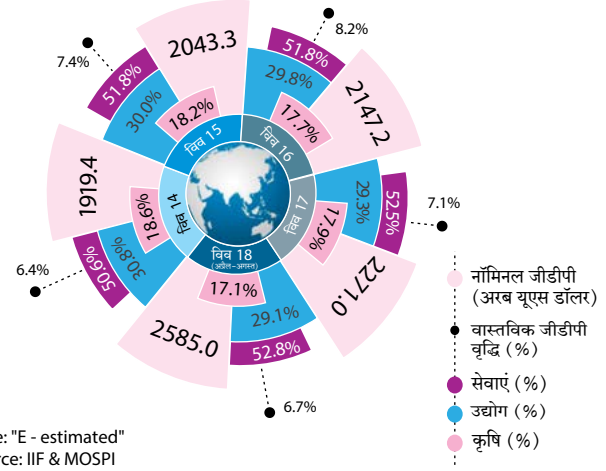

Note: "E - estimated"
Source: IIF & MOSPI

व्यापार और भागीदारी अवसर

व्यापार अवसर

हाइजीन केयर

अल्ट्रा थिन सैनिटरी नैपकिन बनाने के लिए स्वदेशी ऑटोमैटिक मशीन, जो वितरण की लागत कम करने के साथ-साथ ऑटोमेशन और सस्ती लागत पर उत्पादन में सहायक है। उत्पादों की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करती है।

हस्तशिल्प उद्यम

निर्माता के स्वामित्व वाली हस्तशिल्प कंपनी, जहां शिल्पकार न सिर्फ आपूर्तिकर्ता हैं, बल्कि कंपनी के शेयरधारक भी हैं, जो कंपनी की जिम्मेदारियों के साथ-साथ लाभ में भी हिस्सेदारी रखते हैं।

औद्योगिक रसायन

कागज, रंजक और रसायन, रंजक सामग्री, रंजक साबुन उद्योग, टेक्सटाइल, कांच और जल शोधन जैसे क्षेत्रों के उद्योगों को खनिजों तथा रसायनों का निर्यात करने वाली विनिर्माता कंपनी।

ई-कॉमर्स

हथकरघा और हस्तशिल्प सहकारी संस्थाओं और शिल्पकारों को सीधे खरीदारों तक पहुंचाने वाला पहला ऑनलाइन वैश्विक बाजार, जो इन उत्पादों की मार्केटिंग लागत को कम करने के साथ-साथ शिल्पकलाओं की आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक सक्षम और पारदर्शी बनाता है।

बिजली के मीटर

बिजली की खपत मापने वाले ऐसे उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी, जिनसे बिजली की खपत मापने के साथ-साथ बिजली की खपत पर नियंत्रण रखने में भी मदद मिलती है। इन उत्पादों में गैस और बिजली के मीटरों की आपूर्ति सहित हीटिंग और कूलिंग पर नियंत्रण रखने वाले उपकरण शामिल हैं।

कांथा कढ़ाई

फेयर ट्रेड प्रमाणीकृत, गैर-लाभकारी संगठन, उत्कृष्टता का उद्यम, जो शिल्पकारों के सामाजिक विकास की दिशा में काम कर रहा है। इसके उत्पादों में घरेलू टेक्सटाइल्स से लेकर कपड़े, परिधान तथा स्वास्थ्य संबंधी उत्पाद शामिल हैं।

भागीदारी अवसर

परियोजनाओं में अवसर

- म्यांमार का बिजली और ऊर्जा मंत्रालय विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजना के अंतर्गत बिजली ट्रांसमिशन, वितरण लाइनों और ट्रांसफार्मरों की खरीद तथा उन्हें लगाने के लिए टेंडर आमंत्रित कर रहा है।
- ढाका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड ने बांग्लादेश में प्री-पेड इलेक्ट्रिक मीटरों की खरीद के लिए टेंडर आमंत्रित किए हैं। इसकी अंतिम तारीख 26 नवंबर, 2018 है।

निर्यात के लिए अवसर

- सिएरा लिओन से एक आयातक ने भारत से सैनिटरी पैड बनाने वाली मशीन खरीदने में रुचि प्रकट की है। इच्छुक पार्टियां इस संबंध में नीचे लिए गए संपर्क विवरण के जरिए मार्केटिंग सलाहकारी समूह से जानकारी हासिल कर सकती हैं। इच्छुक पार्टियां इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए मार्केटिंग सलाहकारी सेवाएं समूह से संपर्क कर सकती हैं:

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क कीजिए: फोन: 2217 2600, एक्सटेंशन: 2822/2737, फैक्स: 2218 8268, ईमेल: mas@eximbankindia.in